

[Shri Bhagavati]

that the lower middle class people, the poorer section of the people, do not get any advantage even of the socialised capital. The cultivators do not get the advantage of socialised capital at all. Credit should be provided to the cultivators by the State Bank and the other banks. The State Bank should have branches all over the country. I would personally like the banks to be nationalised and their branches should be set up all over the country, so that the agriculturists can get enough credit and can produce more.

In conclusion, I will say this. This is really a gigantic problem—the problem of producing enough for the teeming millions of this country; it is a challenging problem and we have to meet it. I hope, the Government will take adequate measures so that by 1970-71 we can be self-sufficient in food. The Science Advisory Committee of President Johnson has said that, if India wants to be self-sufficient in food by 1976, she would have to increase the crop-yield by 4% annually.

15.59 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair].

We will have to increase 4% annually over 1964 rate of production. Unless we do that, it will not be possible for us to become self-sufficient in food. How we can do that?—that is the problem. Increasing the yield by 4%, will mean that we have to triple the yield from the historical rate which is only 2.36% per year. If we have to do that, we have to irrigate the land, we have to ensure regular, regulated water supply; we have to see that flood is controlled, soil erosion is controlled, fertiliser is supplied, compost manure is supplied as one of my learned friends has just now said or chemical fertiliser is given. All these should go together.

As regards Assam, I would like to say only one thing. Assam's main problem with regard to food production is flood control and conservation of soil. Unless the river Brahmaputra is controlled, it will not be possible for Assam to go ahead. That is a very big task, a major task and I hope Government of India will take it up.

In these scarcity years, particularly some months last year, even in Assam,—where the food condition was not supposed to be so bad, in the tea gardens and certain other places rice could not be supplied and instead of rice, wheat had to be given. But, even in regard to wheat, the supply was very irregular. I am glad that when I took up the matter with the hon'ble Food Minister, he took immediate steps and some wheat was moved to that area and even then, these people suffered very much. So, I would request the Government to see that adequate stocks of wheat are built up in Assam itself so that the people in that State need not have to suffer for want of supply.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is Four O'clock. We shall now take up the next motion standing in the name of Shri Prakash Vir Shastri and others.

15.59 Hrs.

MOTION RE. PAKISTANI INFILTRATION INTO KASHMIR

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

“कि हाल ही में भारी संख्या में पाकिस्तानियों की काश्मीर में घुसपैठ से तथा राज्य में होने वाली अनेक घटनाओं से, जिनसे यह साबित होता है कि पाकिस्तान-समर्थक एजेंट राज्य की शांति भंग करने पर तुले हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे से पैदा हुई स्थिति पर विचार किया जाये।”

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन से भारत स्वतन्त्र हुआ है उसी दिन से पाकिस्तान काश्मीर में तोड़-फोड़ आक्रमण और दुनिया भर में भारत के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहा है। योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने 1965 में काश्मीर में कई हजार प्रशिक्षित घुसपैठिये भेजे जिसका परिणाम भारत और पाकिस्तान संघर्ष के रूप में हुआ। सरकार का दावा यह था कि 1965 में जो प्रशिक्षित घुसपैठिये आये थे, वे वहाँ से वापस चले गये या समाप्त हो गये। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ताशकंद में एक हस्ताक्षर करा कर एक चाल और झांसा दिया था। 740 वर्ग-

मील का वह क्षेत्र जो भारत ने पाकिस्तान से लिया था, जिसमें 270 वर्गमील केवल काश्मीर का ही भाग था, उस पर हस्ताक्षर कराने के लिये जो चाल पाकिस्तान ने चली, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तानी घुसपैठियों की स्थिति हुई—सरकार की दृष्टि में ये घुसपैठिये चले गये लेकिन वास्तविकता यह है कि ये घुसपैठिये भूमिगत हो गये और अण्डरग्राउण्ड हो कर वहां के राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को बरगलाने और दूसरे ढंग से अपना षडयन्त्र पूरा करने का कार्य करते रहे। इससे स्थिति 1965 से भी कहीं अधिक भयंकर हो गई। काश्मीर घाटी में खास कर उन्होंने न केवल छोटी उम्र के बच्चों और किराये के आदमियों को खरीद कर “पाकिस्तान जिन्दाबाद, जिन्ना जिन्दाबाद, अयूब जिन्दाबाद” के नारे लगवाने शुरू कर दिये हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि काश्मीर घाटी में जो बाहर के पर्यटक आते हैं, उन पर भी खुल्लम-खुल्ला हमले की घटनायें वहां पर हुई हैं।

16 Hrs.

हमारी प्रधान मंत्री की स्वर्गीय बूआ श्रीमती कृष्णा हठीसिंह के साथ क्या घटना घटी थी ? यूगोस्लाविया के राजदूत के साथ क्या घटना हुई ? टाटा के जैनरल मैनेजर के साथ वहां पर क्या घटना हुई ? सरकार को शायद उन घटनाओं की अच्छी तरह से जानकारी होगी। मेरे ऐसा कहने का अभिप्राय यह न समझें, कि हमारे पर्यटन मंत्री श्री कर्ण सिंह देश के दूसरे भागों के पर्यटकों को वहां जाने के लिये उत्साहित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता रही बल्कि जहां काश्मीर में 60-70 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष जाते थे, वहां इस वर्ष उनके प्रयास से डेढ़ लाख के लगभग पर्यटक वहां पहुंचे। लेकिन डा० कर्ण सिंह को भी याद होगा कि उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 15 नवम्बर को श्री रामगोपाल शालवाले को बतलाया था कि 3 अक्टूबर को दो यात्री बसों पर, पेंप्पोर और विजाविहार में हमला किया गया जिसके कि

L88LSS/67-9

परिणामस्वरूप वह बसें फिर वापिस श्रीनगर लौट गईं। इस तरीके से पाकिस्तानियों ने यह भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। साम्प्रदायिक तनाव इतना बढ़ा दिया गया है कि जिससे काश्मीर घाटी से हिन्दू छोड़ कर चले जायें। सेना की जो अपनी गाड़ियां हैं जब वह उन सड़कों से निकलती हैं तो उन पर पत्थर फेंकने व धूकने आदि की इसी प्रकार की घटनाएं भारी मात्रा में हुई हैं। पाकिस्तान अब इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि वहां पर हथियार फिर से जमा कर लिये जायें और उसके सहयोग के लिए भी वहां पर एक वातावरण बनाया जा रहा है। मैं अपने इस कथन की पुष्टि में आपको दो-तीन प्रमाण भी देना चाहूंगा। गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण को शायद स्मरण हो नन्दा जी उस समय गृह मंत्री थे और उस समय भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कश्मीर पोलिटिकल कान्फ्रेंस के नेता श्री गुलाम मुहीउद्दीन कारा की ओर से किस प्रकार के पत्र पाकिस्तान के लोगों को लिखे जाते हैं और किस ढंग से पाकिस्तान से सहायता मांगी जाती है ? वह पत्र पूरा नहीं पढ़ना चाहता। वह पत्र बहुत बढ़ा है। उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है जो उनके हस्ताक्षरों से युक्त है। उस पत्र के अन्दर जहां यह है कि आजाद कश्मीर रेडियो से कश्मीर के लिए क्या क्या प्रोग्राम ब्राडकास्ट करें जहां इसमें यह है कि हमने कुछ आदमी इस प्रकार के भेजे हैं जो वहां सहायता करेंगे, वहां उसमें यह भी लिखा है कि आपको कश्मीर के लिए अपने रेडियो से क्या-क्या कार्यक्रम प्रसारित करने हैं ? वहां पर सहयोग के लिए जो उन्होंने उसमें शब्द लिखे हैं और वह भी किस रहस्यमय ढंग से लिखे हैं यह मैं खास तौर से इस सदन को सुनाना चाहता हूँ :

“आपने जो दवा भेजी है वह मिल गई है। उम्मीद है कि मरीजों के लिए वह दवा कारगर साबित होगी लेकिन यह दवा न तो हमारी जरूरत के लिए काफ़ी थी और न ही इससे बरक़त मिली। आप जानते हैं कि यहां अच्छे

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दवाखानों की कमी है। मरीजों की तादाद में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। माजे के अखरा-जात भी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी मिर्कदार में और बरवक्त दवाई न मिलने की वजह से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरीके से चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि दवाई की कमी की वजह से हमें मुश्किल का सामना न करना पड़े इस प्रकार का इंतज़ाम आप करें। . . .”

चिट्ठी* बहुत लम्बी है मैं चाहूंगा कि इसको सदन की टेबुल पर रख दूँ ताकि यह सदन जान जाय और गृह मंत्री जी विशेष रूप से जानें कि वहाँ कश्मीर में कैसा षडयन्त्र रचा जा रहा है। इसमें कश्मीर पोलिटिकल कान्फ़ेंस की ओर से ईद मुबारक के दो कार्डों* के नमूने भी हैं जिनमें एक में मस्जिद का फोटो बना हुआ है और दूसरे पर श्री मुहीउद्दीन कारा की फोटो है। इन कार्डों के ऊपर पाकिस्तान जिदाबाद आदि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लिखे हुए हैं। तीसरा एक और कार्ड का नमूना है जो पोलिटिकल कान्फ़ेंस ने इमदादी फंड के लिए इमदादी रसीदें* जारी की हैं उसमें भी इसी तरह की खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं। इकबाल का यह कलाम उसमें लिखा हुआ है कि हमारा चिराय जलता रहेगा और कोई उसे बुझा नहीं पायेगा। इन कार्डों में इसी तरह की और भी खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं। इसीसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कश्मीर के अन्दर पाकिस्तान ने क्या स्थिति पैदा कर दी है और पाकिस्तान वातावरण को कितना बिगाड़ना चाहता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1961 की जनगणना के आंकड़े में आपसे बतलाते हुए कहना चाहता हूँ कि सन् 1961 की जनगणना में जम्मू-कश्मीर राज्य की जो आबादी लगभग 36 लाख थी। इस 36 लाख की आबादी में से करीब 28 लाख 43 हजार 722 की आबादी

कश्मीर घाटी की है। इसमें 23 लाख 39 हजार 939 के लगभग मुसलमान हैं। पांच लाख 3 हजार 783 के लगभग हिन्दू हैं। पिछले 20 वर्षों में अब तक कश्मीर घाटी में ही नहीं, पूरे जम्मू व लद्दाख के अन्दर कोई घटना इस प्रकार की नहीं घटी जो कि विशेष रूप से वहाँ पर साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली हो या साम्प्रदायिक बैमनस्य को पैदा करने वाली हो। लेकिन 1967 के अगस्त महीने में जो योजनाबद्ध ढंग से अभी पीछे परमेश्वरी नाम की लड़की के अपहरण और मुस्लिम युवक से खबरदस्ती विवाह कांड को लेकर जो भयंकर घटना हुई है उसने कश्मीर को ही नहीं, वरन् सारे भारत को पूरी तरह से हिला दिया। उससे लगता है कि कश्मीर का वातावरण जो पिछले 20 सालों में था अब कश्मीर राज्य की जो सम्प्रदाय निरपेक्ष स्थिति रही उसको भी आघात पहुंचा है। मैं उस केस की तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह केस अदालत में है। मैं उसकी मैरिट्स पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि उस लड़की की बूढ़ी विधवा मां ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवन्तराव चव्हाण के दरवाजे से लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक के दरवाजे को खटखटाया और अपनी नाबालिग कन्या को लौटाने की भीख मांगी। 24 अगस्त को जिस समय मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में फैसला होने वाला था और यह स्थिति थी कि मैजिस्ट्रेट किसी प्रकार से उस नाबालिग लड़की के सम्बन्ध में अपना ठीक निर्णय देंगे तो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को घिरवा दिया गया और मैजिस्ट्रेट वहाँ पर अपना निर्णय न ले सके। विवश हो कर मैजिस्ट्रेट को अपना कोर्ट श्रीनगर छावनी के अन्दर ले जाना पड़ा। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, वह यह कि 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक श्रीनगर शहर में मालूम यह पड़ता था कि कोई राज नहीं है और कोई सरकार यहाँ पर काम नहीं कर रही है। इन दिनों श्रीनगर में जो लूट, छुरेबाजी, हत्या और बलात्कार की

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the documents were not treated as laid on the Table.

घटनायें हुई हैं, उन घटनाओं ने अमृतसर के जालियांबाले बाग के कांड को भी मात कर दिया।

आपको पता होगा कि महिलाओं का जिस समय जलूस निकला उस जलूस के ऊपर तेजाब फेंका गया और पत्थर फेंके गये। श्री यशवन्त राव चव्हाण इस बात की साक्षी देंगे कि जब वह श्रीनगर आये थे तो क्या उनको वहां के कुछ लोगों ने बताया था कि तेजाब फेंकने वालों में जम्मू, कश्मीर राज्य के एक जिम्मेदार मंत्री का लड़का भी सम्मिलित था। जिसने कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर कीं। जो व्यक्ति पुलिस की गोलियों से वहां पर भरे तो उन मृतकों को जब श्मशान भूमि में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो मृतकों के जलूस पर भी इसी प्रकार से हमला किया गया और मृतकों को जनाने तक के अन्दर भी इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई। इन सब कामों को करने में कश्मीर आर्म्ड पुलिस और होमगार्ड्स का पूरा हाथ था। कश्मीर में होमगार्ड्स को खुली छूट इस तरह की हरकतों को करने की दे रक्खी है। मैं श्री यशवन्त राव चव्हाण की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आज श्रीनगर के अन्दर जो एक नई शिव सेना बन गई है उसमें एक का नाम वहां पर होम गार्ड है और दूसरी का नाम फ्रील्ड सर्विस आर्गनाइजेशन है। होमगार्ड्स में 7000 व्यक्ति हैं जिन पर लगभग 60 लाख रुपया व्यय होता है और दूसरी कश्मीर की शिव सेना जिसका नाम फ्रील्ड सर्विस आर्गनाइजेशन है उसके 2000 सदस्य हैं जिन पर कि 30 लाख रुपया व्यय होता है। करीब 90 लाख रुपया इन पर खर्च किया जा रहा है। इनका काम क्या है? कांग्रेस के बाहर से गये नेताओं की सभा में हाजिरी बढ़ाना उनकी सभाओं में भीड़ करने का काम वह करते हैं। जनता पर वह दबाव डालते हैं और उसे चुनाव के अन्दर काम में लाते हैं। इसी प्रकार के जो दंगे फसाद वहां होते हैं उसमें अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर ऐक्शन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस लड़की के कांड को लेकर

जो वहां पर बारदातें हुई हैं मैं उनके विस्तार में न जाकर संक्षेप में आपको कहूं तो केवल इतना कह सकता हूं कि इस सारे कांड में 57 बार वहां पर लाठी चार्ज हुआ। 143 बार टियर गैस, अश्रु गैस का इस्तेमाल हुआ। 5 बार महिलाओं पर तेजाब और पत्थर फेंक कर उन्हें घायल करने की घटनाएं हुईं। 5 बार जलूसों पर पथराव हुआ। 2,075 व्यक्ति घायल हुए। 6 आदमियों की मृत्यु हुई। 15 बार घर और दुकानें जलाई गईं। 12 बार लूटी गईं। इस तरह की घटनाएं यहां पर हो रही हैं और इन तमाम घटनाओं के बाद भी अगर भारत सरकार यह समझती है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बिलकुल ठीक है और पाकिस्तान अपने अनुकूल वातावरण बनाने में सफल नहीं हुआ है तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी सतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है? जहां यह हालत हो गई थी कि जलूसों पर तेजाब फेंका जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थीं, लाठियां चलाई जा रही थीं, वहां इंसानियत को भी दया उत्पन्न हो सकती थी। करुणा से मानवता का हृदय भी पिघल सकता था। लेकिन कश्मीर में जहां श्रीनगर की गलियों में यह सारी घटनाएं घटीं वहां इंसानियत ताक में रख दी गई थी। जो सरकारी अस्पताल थे वहां घायलों को भरती करने से इंकार कर दिया गया। जम्मू, कश्मीर की जो रेडक्रॉस सोसाइटी थी उसने घायलों को उठाने से इंकार कर दिया। उनके द्वारा घायलों को एम्बुलेंस देने तक से इंकार कर दिया गया।

अब यह कहा जा रहा है कि इस कांड के अन्दर जो घायल हुए थे उन की हम क्षतिपूर्ति करेंगे। लेकिन यह क्षतिपूर्ति उन्हीं लोगों की होगी जो सरकार अस्पतालों में भरती हुए, अन्वों की नहीं। पर सरकारी अस्पतालों में घायल होने वालों के भरती होने का यह नमूना रहा है जो कि मैंने अभी आप से निवेदन किया। वहां के लोगों की सब से बड़ी मांग आज यह है कि सारे कांड की जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के किसी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर के निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उच्चस्तरीय जांच कराई जाय जिस से कि वस्तुस्थिति का देश को भी पता लगे और सरकार को भी पता लगे। लेकिन इस के साथ-साथ गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण से एक सीधा सवाल भी मैं करना चाहता हूँ कि अब हिन्दू कश्मीर घाटी में रहें या वहां से चले जायें। अगर हिन्दू कश्मीर घाटी में रहें तो उन की सुरक्षा की आप की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है? आप जब 2 सितम्बर को कश्मीर गये आप ने उन को क्या आश्वासन दिया था? 3 सितम्बर को आप के और जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री सादिक साहब का जो संयुक्त वक्तव्य निकला था उस वक्तव्य के अन्दर क्या बात थी? आप ने किस प्रकार का आश्वासन दिया था? मैं चाहूंगा कि आज गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण बतायें कि उन का आश्वासन वहां पर पूरा हुआ या नहीं हुआ? आज तक उस अभागी विद्यवा मां की लड़की की स्थिति क्या है और वह कहां है? जरा श्री यशवन्तराव चव्हाण इस सदन के द्वारा जम्मू कश्मीर के निवासियों और देशवासियों को बतायें? भारत सरकार के गृह मंत्री के आश्वासनों की कोई कीमत है या नहीं? सरकार की कश्मीर नीति में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ कि आज आप स्पष्ट रूप से संसद और देश को बतलायें कि क्या आप की नीति वही है जो 20 वर्ष पहले थी या 20 साल के बाद आप की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? अगर श्री राजेश्वर राव की नीति में परिवर्तन हुआ है तो उन की बात तो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आज रूस के अन्दर कोसिगिन हैं आज रूस के अन्दर स्वरुश्चेव नहीं हैं। स्वरुश्चेव के समय में कश्मीर के सम्बन्ध में उन की नीति और थी और आज कोसिगिन की नीति कुछ और है।

सादिक साहब की बात भी एक बार समझ में आ सकती है, जिन के चिन्तन की

धारा लगभग वही है। यही सादिक साहब थे, याद होगा कांग्रेस के सदस्यों को, डा० रामसुभग सिंह को, जब 20 अप्रैल, 1964 को कांग्रेस एम० पी० के अन्दर वह बयान दे कर गये थे कि संविधान की धारा 370 लगी रहने से जम्मू और कश्मीर के अन्दर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। उस धारा को एक दम हटाया जाये। आज वही जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री सादिक साहब हैं जो कहते हैं कि धारा 370 के हटायें जाने से कश्मीर में बहुत भारी विनाश हो जायेगा। उन की बात समझ में आ सकती है क्योंकि उन के सोचने का ढंग दूसरा है। यह भी मैं समझ सकता हूँ जम्मू और कश्मीर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भीरू कासिम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वक्तव्य दिया था, वह वक्तव्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने छपा है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। 31 अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर विधान सभा में जो वक्तव्य दिया उस में उन्होंने सारे कांड की जिम्मेदारी इस पर डाली कि देश के दूसरे हिस्सों में इसी प्रकार की घटनायें हो रही हैं, यह उसी की प्रतिक्रिया है। कासिम साहब के, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष वहां हैं, इस प्रकार के बयान दें। सुनने वाले और कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं, मेरे पास कोई अधिकृत प्रमाण तो नहीं है कि एक बार क्रोध में आ कर उन्होंने यह भी कह दिया कि हम ने 1947 में कवाइलियों का सामना किया और 1967 में बनिहाल की ओर से आने वाले शब्दों का भी सामना करेंगे। परन्तु यह सारी बातें मैं एक बार समझ सकता हूँ। लेकिन जो मेरा स्पष्ट सवाल है, श्री यशवन्तराव चव्हाण से, वह यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंगला बांध पर अय्यूब साहब को जो वधाई दी, उस का क्या मतलब है? उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंगला बांध के उद्घाटन समारोह में भारत के हाई कमिश्नर के जाने के सम्बन्ध में वकालत करते हुए यहां पर कहा कि भारत

पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है। आखिरकार आप के इन वक्तव्यों के पीछे क्या रहस्य है? अगर कोई विशेष रहस्य है तो आप सदन को बतलाइये, देश को बतलाइये कि आप की इच्छा क्या है।

वह जो आप के 16 हजार रुपये माहवार के मेहमान दिल्ली में बैठे हुए हैं जम्मू काश्मीर के क्या उन को आप छोड़ रहे हैं? अगर आप छोड़ने को तैयार हैं तो सच्ची बात बतलाइये कि आप शोख को छोड़ना चाहते हैं या काश्मीर को छोड़ना चाहते हैं। इरादे आप के क्या हैं? अगर यह स्थिति आप की नहीं है तो मैं दूसरी बात आप से पूछना चाहता हूँ बड़ी स्पष्ट भाषा में कि आज अमरीका और रूस के दबाव के कारण भारत सरकार कहीं अपना मन तो डुलाने नहीं जा रही है? अपने स्टैण्ड में परिवर्तन करने तो नहीं जा रही है? कहीं भारत सरकार की नीति यह तो नहीं है कि पहले शोख को छोड़ा जाये, और कुछ दिन के बाद काश्मीर घाटी को उन के हवाले कर दिया जाये। पहले कुछ विशेष विषय दिये जायें और धीरे-धीरे इसी प्रकार से उन के सब इरादे पूरे किये जायें? अगर यह स्थिति है तो मैं श्री यशबन्तराव चव्हाण से पूछना चाहता हूँ, और मैं ही नहीं, देश पूछना चाहता है कि फिर आप ने इस अभाग्य मुल्क का अरबों रुपया जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में क्यों पानी की तरह बहाया? हजारों बहनों के मुहाग का सिन्दूर आप ने क्यों पोंछा? अगर आप को इसी तरह की स्थिति पर पहुँचना था? कांग्रेस के माथे पर दो पाप ऐसे हैं, आप जिनको सहस्त्राब्धियों तक नहीं धो सकेंगे। एक पाप भारत के विभाजन का और दूसरा पाप देश में भाषावार प्रान्तों के निर्माण का। वराय मेहरबानी इतिहास का तीसरा कलंक अपने माथे पर मत लगाइये कि इस प्रकार से अरबों रुपये व्यय करने के बाद और इतने वलिदानों के बाद काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति भी आ गई। मैं आप से एक बात और कहना चाहूँगा। जम्मू और काश्मीर राज्य की जो स्थिति है वह जहाँ भारतवर्ष

के लिये चुनौती है वहाँ जम्मू और काश्मीर राज्य का आन्तरिक वातावरण भारत में केन्द्र की कांग्रेस सरकार के लिये एक अग्नि-परीक्षा भी है। मैं अग्नि-परीक्षा का शब्द जान बूझ कर प्रयोग कर रहा हूँ। अग्नि-परीक्षा इस लिये कि आज जम्मू और काश्मीर विधान सभा में 75 सदस्य हैं। उन में से दो स्थान खाली हैं। 73 सदस्यों में से विधान सभा में 26 सदस्य वह हैं जो निर्विरोध चुन कर भेजे दिये गये हैं। 13 व्यक्ति विरोधी दल के हैं। इस तरह 73 सदस्यों में से चौतीस शेष आदमियों को बहुमत में मान कर सरकार उन के हाथों में दी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर पश्चिम बंगाल और यहाँ की स्थिति में अन्तर क्या है? पश्चिम बंगाल के केस का आप इस लिये समर्थन करते हैं कि वहाँ पर चीन समर्थक नारे लगने लगे थे, हिंसा की घटनायें बढ़ गई थीं। मैं श्री चव्हाण साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू और काश्मीर में पाक समर्थक नारे नहीं लग रहे हैं? हिंसा, लूट-पाट, तोड़-फोड़ और बलात्कार की घटनायें वहाँ नहीं हो रही हैं? अगर इस प्रकार के काम करने पर आप बंगाल को संभाल सकते हैं, बंगाल का पक्ष ले सकते हैं, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति उस से भी बदतर है। श्री भगवान सहाय, जो इस समय वहाँ राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार को किसी प्रकार की कोई सिफारिश राष्ट्रपति शासन की करने के लिये नहीं जा रहा हूँ। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के राजनीतिक वक्तव्य देने की आदत मत डालिये, वरना यह आगे चल कर आप को और देश को भी भारी पड़ने वाली है। वह स्थिति को जान-बूझ कर अपनी आंखों से ओझल करना चाहते हैं। एक ही तरीका जम्मू और काश्मीर को बचाने का है, और वह यह कि भारतीय संविधान की गली-सड़ी घाटा 370 को एकदम समाप्त कर के जम्मू और काश्मीर में

[भी प्रकाशबीर शास्त्री]

राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। यही जम्मू और काश्मीर की समस्या का समाधान है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो-तीन बातों और भी कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि राज्य की आन्तरिक स्थिति बिगाड़ने के लिये दोषी है कौन? जम्मू और काश्मीर की जो सरकार है उसी की वजह से राज्य के अन्दर इस प्रकार की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। 1965 का संघर्ष क्यों हुआ? 1965 के संघर्ष से पहले के कुछ जिम्मेदार पाकिस्तानी अधिकारियों को जिनमें से मैं एक-एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू और काश्मीर में आने और ठहरने का मौका दिया गया। एक हैं आगा शौकत, जो डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्फर्मेशन, पश्चिमी पाकिस्तान थे, वहाँ पर आये और आ कर रहे। दूसरे हैं ख्वाजा गुलाम मोहम्मद, यह आजाद काश्मीर के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और अब पाकिस्तान के डाइरेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैं। वह 1965 से पहले आये और आ कर वहाँ रहे। तीसरे हैं आशिक हुसेन, यह भी 1947 से पहले सीपर में मुंसिफ थे और अब पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जज हैं। यह उन दिनों वहाँ पर आये। चौथे हैं शेख मुहीउद्दीन जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स आफिसर हैं, वह भी आये। इसी तरह से गुलाम मुहम्मद, जो पाकिस्तान में जज हैं, वहाँ आये। इस प्रकार के खतरनाक व्यक्ति वहाँ आ रहे हैं और खुल्लम-खुल्ला रह रहे हैं तथा जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। भारत सरकार कानों में तेल डाले हुए बैठी है और समझती है कि जम्मू और काश्मीर में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। क्या यही तरीका है काम करने का?

आप ने जो कांग्रेस वहाँ बनाई है, उस की स्थिति क्या है? विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता किस प्रकार से वहाँ की कांग्रेस सम्प्रदायवाद और साम्यवाद का गढ़ बन चुकी है। मेरे पास एक लम्बी लिस्ट है, जो कि

प्लेबिसाइट फ्रंट के लोगों की है। जम्मू और काश्मीर की तहसील कांग्रेस का प्रेजिडेंट कौन है, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का प्रेजिडेंट कौन है, यह अगर आप देखें तो आप को अनुमान हो जायेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। अगर आप चाहें तो मैं उस को यहाँ टेबल पर रख सकता हूँ। क्या इस तरह की स्थिति में आप जम्मू और काश्मीर को बचायेंगे। मैं आप से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप के पास कोई इस प्रकार की सूचना भी है कि 1947 में कुछ इस प्रकार के लोग गिरफ्तार किये गये थे जो कि उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, और आज वही राज्य के अन्दर बड़े-बड़े ओहदों पर बिठला दिये गये हैं? क्या आप के पास इस प्रकार की जानकारी है कि आज जनमत संग्रह भोवों के जो लोग हैं वह कांग्रेस में घुस कर पीछे से कमर में छुरा भोंकने के लिये तैयारी कर रहे हैं? क्या आप के पास इस प्रकार की जानकारी है कि साम्यवादियों के बड़े-बड़े नेता आज जम्मू और काश्मीर में जा कर राजकीय मेहमान बनते हैं और वहाँ जा कर अपनी सारी योजनायें बनाते हैं।

मैं इन तमाम बातों से भी आगे बढ़ कर एक और खतरनाक चीज आप की निगाह में लाना चाहता हूँ। आप हिन्दुस्तान से जो भारी मात्रा में अन्न जम्मू और काश्मीर में भेज रहे हैं या जो कपड़ा सस्ते दामों पर भेजा जा रहा है, वह उस के सम्बन्ध में है। मैं आप को एक-एक वर्ष के आंकड़े नहीं देना चाहता फिर भी तीन वर्ष के कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूँ। उस से आप सही स्थिति का अनुमान लगा सकेंगे। 1963 में राज्य का उत्पादन था 641 हजार टन और केन्द्रीय सरकार ने जो अन्न भेजा वह था 62 हजार टन। 1964 में राज्य का उत्पादन था 603 हजार टन और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अन्न दिया गया वह था 63 हजार टन। 1965 में राज्य का उत्पादन था 533 हजार टन और केन्द्र से गया 1 लाख 51 हजार टन। इसी तरह से 1966 में यहाँ से गया 1 लाख 29 हजार

टन । अगर आप इस में राज्य से पैदा हुए अन्न और केन्द्र द्वारा भेजे गये गेहूँ को मिला लें और फिर काश्मीर की आबादी में उस को बराबर बराबर बांट दें, तो किसी भी व्यक्ति को जम्मू काश्मीर और लद्दाख में दूकानों के सामने लाइन लगा कर खड़े होने की जरूरत नहीं है । मेरा सीधा-सा सवाल है कि वह गल्ला कहां गया जो यहां से सस्ते दामों पर भेजा गया ? आप यहां से भेजते हैं जम्मू और काश्मीर के लिये, लेकिन वह गल्ला या उस का अधिकांश भाग सीमा से हो कर पाकिस्तान को पास हो रहा है जब कि आप यह सोचते हैं कि आप जम्मू और काश्मीर के लोगों की मदद कर रहे हैं ।

आप इस चीज से भी सावधान हो जाइये कि चीन और पाकिस्तान ने एक नया प्लेन तैयार किया है । वह इस्लामाबाद को आक्सार्ड चिन से मिलाने का षड्यन्त्र कर रहे हैं और इस प्रकार की प्लेन से पाकिस्तान और चीन को नये मार्ग से मिलाया जा रहा है । दूसरी तरफ इधर यह स्थिति है कि जो जम्मू और काश्मीर के तपे हुए और परखे हुए नेता हैं, जो कि बगल में कांग्रेस की बेंचों पर बैठते हैं लद्दाख के माने हुए नेता हैं, उन की कोई सुनता नहीं है । कुशक बकुल जैसा व्यक्ति यहां बैठा है । पिछले सत्र में प्रेस को एक बक्तव्य उन्होंने दिया था जो लद्दाख के लोगों के मन की टीस बताता था । मैं जानना चाहता हूं क्यों उन के मुकाबले में 16 साल के लड़के को ला कर उन की पर्सनेलिटी को चैलेन्ज किया जाय और ऐसे व्यक्ति को, जिस के लिये सारा लद्दाख माथा झुकाता है, आघात पहुंचाया जाये ? इन ही तरीकों से आप जम्मू और काश्मीर की रक्षा करना चाहते हैं ? क्या इस तरह से आप देश के मस्तक काश्मीर को बचा सकेंगे ?

मैं ज्यादा आगे न बढ़ता हुआ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हुआ कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं । सब से पहला सुझाव यह है कि संविधान की धारा 370 को समाप्त

कीजिये, दूसरे काश्मीर में राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू कीजिये और अगस्त कांड की निष्पक्ष जांच कीजिये । इस के अतिरिक्त मैं यह सात सुझाव और देना चाहता हूं :

- (1) पाकिस्तानी तत्वों का सफाया करने में केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार की दया न दिखाए;
- (2) जो नाबालिग हिन्दू लड़की है उसे वापस किया जाये, जिससे जम्मू और काश्मीर राज्य के अन्दर साम्प्रदायिक तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, उस में कमी हो;
- (3) वहां पर जो अकर्मण्य और दोषी अधिकारी हैं, जिन को मंत्री महोदय भी जानते हैं, उन का एकदम तबादला कर दिया जाये, वना राज्य की स्थिति बद से बदतर होती चली जायेगी;
- (4) काश्मीर आर्डर्ड पुलिस की नये सिरे से जांच कराई जाये और यह देखा जाये कि कहीं देश-विरोधी तत्व तो उसमें प्रविष्ट नहीं हो गए हैं;
- (5) होम गार्ड्स और फील्ड सर्विस आर्गनाइजेशन को तत्काल समाप्त किया जाये । इस तरह से मुख्य मंत्रियों को नई-नई सेनायें बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये;
- (6) अगस्त कांड के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाये; और
- (7) जम्मू, काश्मीर और लद्दाख को उन की जनसंख्या के अनुपात से नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाये, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं और उस के साथ ही मैं विशेष रूप से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि बीच में मैंने टेबल पर रखने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

के लिये कुछ कागजात भेजे, लेकिन आप ने हाथ हिला दिया। वे इतने गम्भीर डाकुमेंट्स हैं कि अगर देश और सदन उन से परिचित नहीं होंगे, तो उन को जम्मू और काश्मीर की वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पायेगा। मेरा अनुरोध है कि आप उन को सदन की टेबल पर रखने की इजाजत दें। इस में कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं उन को यहाँ पढ़ चुका हूँ। इस लिये उन को सदन की टेबल पर रखने की अनुमति आप को देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member knows that there are certain rules regarding placing documents on the Table of the House. If the hon. Member so desires, I will ask the office to see them and then they might be kept in the Library, not here on the Table.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Placing in the library is not the same thing as placing it on the Table.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I meant was, they will be examined by the Secretary...

SHRI RANGA : Please do not bring in the Secretary in this. Whatever is to be done has to be done in the name of the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, the Chair will examine them. The authenticity of the documents, whatever documents are bandied about—some Members say that they will place them on the Table—has to be verified. It will have to be verified whether it is proper or not to place them on the Table. According to rules we have to examine every aspect and then only I can give the final permission. That does not mean automatically I will give the permission. Motion moved :

“That the situation arising out of the serious threat to national security forced by the recent influx of Pakistani infiltration into Kashmir and the spate of incidents in

the State evidencing a determined bid by pro-Pak agents to subvert the peace of the State, be taken into consideration.”

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the problem of Kashmir whether it relates to Pakistani infiltration or anti-social elements can, in my opinion, be best discussed in the broader context of political, social and economic atmosphere prevailing in the Valley for the last twenty years-after independence and more particularly, after the Sadiq Government was imposed on the State.

The complicated nature of this Kashmir problem, in my opinion, today reflects the economic frustration and resentment against the corrupt Government in the State, on the one hand, and the weak central administration and the various political blunders made by the Indian Government, on the other, over the last twenty years. Although India has spent crores of rupees in the Valley most of this money has been drained out and spent in the form of giving subsidies and doles, and it is very unfortunate to find, going into the Valley and travelling around, that not even one meaningful employment opportunity has been created in the course of the last twenty years. Kashmiris, by and large, remain today as poor as before. If you go round the Valley you see opportunities of tannery, of timber work, orchards and various other industries which can be developed. But, unfortunately, none of these industries have been developed in twenty years and money has been wasted.

On the other hand, with the growth of population and more and more educated young men coming out of colleges resentment has grown. The educated youth became resentful about not getting employment and became frustrated against the Government. Against this political background, against this economic background, after the recent elections a Congress Government was imposed upon the State. Congress was a new party. On account of the wrong leadership, on account of the party not being associated with the national senti-

ments of the State, it could not get popular backing. Mr. Sadiq, his previous history known to most of us, being sometimes associated with anti-social activities, had permitted himself to be dragged in different directions in order to beg popularity. Sometimes he permitted to be dragged into the direction of favouring a certain particular community, sometimes some other community. As a result, his administration completely failed. Under this administration, we know what happened in the last elections. As my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri has stated, as many as 26 members were elected uncontested. It is known to all the Members of the House, including the Home Minister, Shri Chavan, the manner in which the nominations were rejected, the nomination papers of non-Congress party members were rejected, the manner in which the Government machinery was used only to see that the Congress Party candidate, the party which was imposed upon this State, gets elected into the State Legislature.

SHRI RANGA : Even Dr. Karan Singh had to protest against it.

SHRI D. N. PATODIA : With this background, I will come to the recent events, recent disturbances, recent pro-Pakistani incidents and raising anti-Indian slogans which have appeared there, as a clear reflection of weak and corrupt and ineffective administration. The communal trouble, which never happened in the Kashmir Valley during the last twenty years, why did it happen now? Pandit community, Muslim community and Hindu community, they used to live together in harmony for the last so many years. Why all of a sudden, about four months back they became so communal in character that there were excesses committed by all the communities? The problem of the Pandit community, relating to the incident of the girl, pointed out by Shri Prakash Vir Shastri was, in my opinion, a pure and simple administrative problem, which could have been tackled very effectively by acting promptly and taking stern action. It was deliberately, on account of the weak administration, given a communal colour and excesses

were committed and brutal assaults were made on females and ladies and children, never heard in the history of democracy anywhere in the world. Similarly, thereafter, when the turn came of the Muslims, equally brutally they were lathi-charged, equally brutally firing was done on that community. It is the Sadiq Government which is unpopular, not only with the Hindus, not only with the Pandit community but also with the Muslims; the entire Kashmir community hates this Government and the entire Kashmir community feels today that the Sadiq Government is not in a position to deliver the goods.

Now, with this background, comes the problem of Pakistani infiltration, comes the problem of new anti-national, anti-social elements raising their heads. It is not very correct to say that the people who crossed over the borders in 1965 are now coming back and they are Indian citizens and, therefore, they are loyal. Their loyalty is very much to be doubted. The people who crossed over the frontiers two years back, who were brain-washed by Pakistan for two years and possibly bribed by paying money, their loyalty cannot be taken for granted. They were waiting for an opportune time. It was a deliberate game to select a proper timing for these anti-social elements to be migrated back to Indian territory, and they found that on account of the weak administration of the Sadiq Government, this is the proper time when they should avail the opportunity to go to the Indian territory. On that provocation, backed by Pakistani money and brain-washed by the Pakistani elements they are coming back to India with the ultimate object of creating trouble and because they are Kashmiris, speaking the same language and having the same habits, they cannot be identified. So, for the first time, anti-national, anti-social, pro-Pakistani elements are raising their heads on such a magnitude in this State, which was never known before. For the first time, people are parading in the streets, shouting "Ayub zindabad", shouting "Indian leaders murdabad", which has never been heard

[Shri D. N. Patodia]

before. But, then, it has been tolerated and the Sadiq Government has proved to be absolutely ineffective.

For the first time, a very peculiar situation arose in Kashmir. The troops and police belonging to the two different States, on account of wrong handling by the administration, were permitted to be carried away by communal frenzy. Still, we are hoping that this Government will be able to deliver the goods. I beg to submit that under these circumstances a grave situation has arisen in this State which demands very effective administrative handling, which demands a clean and pure administration, which demands anti-social elements to be suppressed, checked and curbed.

This Government is not capable of doing it. A situation has arisen when we must all rise above the level of parties. For the sake of Kashmir State a leadership belonging to all the parties, truly national in its character, must emerge. A government under that national leadership must function in that State. That government alone will be effective and will be able to deliver the goods. I hope that the hon. Home Minister will accept these suggestions.

श्री भ्रमृत नाहटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर का नाम लेते ही हमारे दिलों की अंतरतम गहराइयों को वह छू लेता है। सिर्फ इस लिये नहीं कि वह इस धरती पर स्वर्ग है, सिर्फ इस लिये नहीं कि वह हमारे देश का भाग है सिर्फ इस लिये नहीं कि वहां की जनता ने बहादुरी से वहां पर मुजाहिदों से टक्कर ली है बल्कि इस लिये भी कि वह एक जिन्दा जाति का सबूत है हमारे हिन्दुस्तान के सब से शानदार आदर्श का जिसे हम कहते हैं धर्म-निरपेक्षता काश्मीर एक ऐसी धरती है हमारे देश की जहां हमेशा से हिन्दू और मुसलमान सभी जातियों, धर्मों और सम्प्रदायों के लोग बराबर हिलमिल कर रहते आये हैं आज हम सब देशवासियों के लिये एक बड़े शर्म की बात है, जिस से कि हमारा सिर झुक जाता है कि उस साम्प्रदायिक एकता को तोड़ने की

कोशिश की जा रही है। वहां पर एक बार फिर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर हमारे देश का एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र बन गया है। मैं यह मानता हूँ कि काश्मीर में पड़्यंत्र हो रहा है न सिर्फ हमारे देश के लोगों द्वारा, न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा, पाकिस्तानी जासूसों द्वारा बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो कि सक्रिय एजेंसियां हैं, जिसमें सी० आई० ए० भी शामिल हैं वह लोग भी सक्रिय रूप में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि काश्मीर में उपद्रव खड़े किये जायें, साम्प्रदायिक दंगे कराये जायें, साम्प्रदायिक झगड़े फैलाये जायें और ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि काश्मीर की स्थिति संभाली न जा सके और फिर यह कहा जाये कि काश्मीर हिन्दुस्तान का नहीं है, काश्मीर पाकिस्तान का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उधर बैठने वाले दोस्त कौटिल्य और मैकाइविले को अपना गुरु मानते हैं। मैं उन को कहुंगा कि वह एक सब से बड़ा सबक कौटिल्य और मैकाइविले से जो लें वह यह कि आप ऐसा कोई काम न करें जिस से कि दुश्मन को फायदा पहुंचे। आप के इस प्रकार के प्रचार से पाकिस्तान की जो प्रापेण्डा मशीनरी है उस में आप तेल डाल रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं। आप यह बताना चाहते हैं कि आप के दिलों में यह विश्वास नहीं है कि मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति वफादार हो सकते हैं। अगर जो आप दिल में मानते हैं वह सही है तो फिर काश्मीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान की धरती पर, काश्मीर की धरती पर रहनेवाला चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुसलमान हो वह हमारा प्यारा भाई है और वह इस देश पर उतना ही हक रखता है जितना दूसरा कोई रख सकता है और इस लिये काश्मीर हमारा है। अगर आप यह समझते हैं कि काश्मीर में रहनेवाले जो घुसपैठिये हैं वह देश के प्रति सिर्फ बही गद्दार हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना

चाहता हूँ कि गद्दार का कोई मजहब नहीं होता। जो गद्दार है वह न हिन्दू है न मुसलमान है, वह गद्दार है। बहुत मुसलमान है, आज इस खूबसूरत घाटी की साम्प्रदायिक एकता को खत्म करने के लिये जिस प्रकार का जहर उगला जा रहा है, उस के प्रति मैं अपने दोस्तों को सावचेत करना चाहता हूँ, हो सकता है, मैं नहीं इनकार करता कि कहीं कुछ ज्यादाती हुई हो, पुलिस पुलिस है चाहे वह काश्मीर की हो चाहे बिहार की हो, आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये, क्या रांची में जब दंगे हुए, भाषा के सवाल पर और वहाँ शांति व्यवस्था भंग हो गई और वहाँ बुरी तरह से लोगों को गोलियों से भुना गया, तो क्या आप कहेंगे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये ? मैं आप से पूछना चाहूँगा कि कौनसा राज्य है हमारे देश में कि जहाँ वक्तन-फवक्तन इस प्रकार के सवाल नहीं उठ खड़े होते हैं जहाँ वक्तनफवक्तन इस प्रकार के कुछ दंगे की या अशांति की स्थिति पैदा नहीं होती ? वहाँ की सरकार जो संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है कौनसी ऐसी अव्यवस्था आ गई, कौनसा ऐसा संवैधानिक संकट आ गया जिससे आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये ? सिर्फ यही चाहते हैं न कि पाकिस्तान कल को यह कहे कि देखो हिन्दुस्तान ने काश्मीर में जम्हूरियत को खत्म कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के सामने यह कहेगा कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दू साम्राज्यवाद के लोग जम्हूरियत को काश्मीर में जिन्दा नहीं रहने देना चाहते। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह आप अपने दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। आप के पास कोई शिकायत हो, कोई ज्यादाती हुई हो किसी के साथ जुल्म हुआ हो तो आप बेशक सरकार के सामने उसे लायें लेकिन ऐसी कोई बात न करें, कोई वातावरण ऐसा पैदा न करें कि जिस से उस घाटी की साम्प्रदायिक एकता खत्म हो और आप अपने दुश्मन के प्रचार की मशीनरी में और अधिक तेल डालें और आप जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे दुश्मन के हाथों में खेलें।

आप कहते हैं कि 370 हटा दी जाय। शनैः शनैः बराबर धीरे-धीरे काश्मीर और हिन्दुस्तान की एकता नजदीक आती जा रही है। आज वहाँ सदरे रियासत नहीं है, गवर्नर है। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये। बराबर काश्मीर नजदीक आ रहा है। आज एलेक्शन कमीशन का क्षेत्र काश्मीर तक बढ़ाया गया है। आज काश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में मुख्य मंत्री हैं वैसे ही काश्मीर में भी मुख्य मंत्री है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ की जनता और हिन्दुस्तान की जनता एक-दूसरे के नजदीक आये, और हम दिलों से कह सकें कि काश्मीर की जनता के दिल और सारे हिन्दुस्तान की जनता के दिल एक हैं तो आप उन के दिलों को जीतिये। केवल विधान की धाराओं को मिटाने से आप वहाँ की जनता का हृदय नहीं जीतेंगे। बल्कि आप अपने इन कार्यों से, अपने इस जहरीले प्रचार से उन लोगों को यह बता रहे हैं कि जैसे वह हमारे नहीं हैं, जैसे वह अपने से दूर हैं। आप अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि आप का काश्मीर की जनता में विश्वास नहीं है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी दोस्तों से एक बार फिर अपील करूँगा कि वह बहुत गम्भीरता से इस सवाल पर सोचें और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिस से वह साम्प्रदायिक आग में और ज्यादा घी डालें।

श्री य० द० शर्मा (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि काश्मीर के संबंध में यहाँ पर पीछे गत 4 अप्रैल की कार्यवाही में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और इसी तरह से 17 मई की कार्यवाही में गृह मंत्री श्री नन्दा जी ने कुछ वक्तव्य दिये थे और एक "सब अच्छा है" का बड़ा अच्छा प्रभावशाली चित्र खींचा गया था कि सब घुसपैठिये लौटा दिये गये हैं, अब काश्मीर के अन्दर सब अच्छा है, सब प्रकार की शांति है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कुछ ऐसे कल्पना के जगत में रहने की आदी हो गई है अथवा

[श्री य० द० शर्मा]

इस सारे सदन को या देश के लोगों को धोखा देना उस की आदत का हिस्सा बन गया है, कह नहीं सकता कुछ । स्थिति दिन-प्रतिदिन इस प्रकार बिगड़ती चली जा रही है और आज जैसी काश्मीर के अन्दर विस्फोटक स्थिति है, माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आप के सामने उस का एक चित्र रखा, मैं यह समझता हूँ कि सरकार सब प्रकार से वहाँ की स्थिति को संभालने में असमर्थ है । वहाँ के प्रदेश की सरकार जो है उसे तो हम निश्चित रूप से वहाँ की स्थिति को संभालने के लिये अयोग्य, अक्षम और सब प्रकार से अप्रभावी महसूस करते हैं लेकिन वड़ा दुःख उस समय होता है जब केन्द्र की सरकार को भी बिलकुल इस मामले में दर्शक के रूप में बैठा हुआ हम देखते हैं। पीछे जितनी स्थिति काश्मीर के अन्दर हुई केन्द्र की सरकार कुछ नहीं कर पाई । हमारे देश की प्रधान मंत्री महोदया पूर्वी योरप की यात्रा पर गई हुई थीं । माननीय गृह मंत्री महोदय यहाँ किसी मौन व्रत की साधना उन दिनों कर रहे थे और काश्मीर जल रहा था । एक ऐसी विचित्र स्थिति है । मेरे पास कुछ चीजें जन्होंने दी हैं । यह एक पत्र है कहीं किसी विदेश से आया है काश्मीर यूनिवर्सिटी के लिये और इस पर पता लिखा है—काश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, काश्मीर, पाकिस्तान । अब आप देखिये, पाकिस्तानी एजेंसी किस प्रकार का संसार के अंदर प्रचार कर रही है और हमारे प्रचार विभाग के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं ? वह लोगों को पता नहीं क्या समझा रहे हैं ? माननीय स्वर्ण सिंह ने यहाँ पर बताया कि सब घुसपैठिये वापस भेज दिये गये । कहीं एकाध इक्के-दुक्के भूले-भटके किसी जंगल बगैरह में बैठे हों तो वह बात दूसरी है लेकिन और वहाँ सब ठीक है । मगर मैं समझता हूँ कि आज वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही सोचनीय है । इस समय कोई भी आदमी श्रीनगर की घाटी में जाता है तो उस को ऐसा पता नहीं लगता कि यह घाटी भारत का हिस्सा है ।

उसे यह प्रतीत होता है कि यह पाकिस्तान का कोई नगर बन कर रह गया है । ऐसी वहाँ की स्थिति है । जहाँ का ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल पैरालाइज्ड है । जो चीज श्रीनगर में 4 अक्टूबर को हुई, सेना की तीन गाड़ियों पर खुलेआम बारामूला के पास आक्रमण किया गया, उन गाड़ियों को बचाने के लिये पुलिस ने गोली चलाई और प्रो-पाकिस्तान एलीमेंट के दो व्यक्ति मारे गये तो उस के बाद 4 अक्टूबर की हड़ताल काल दी गई और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मीर कासिम उस काल को देते हैं । लोगों को कहा जाता है कि घाटी को हिन्दू बनाया जा रहा है । उस के अन्दर सारे के सारे नेता शामिल होते हैं और वहाँ के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों ने जो कुछ वहाँ किया, जिस तरीके पर श्रीमती कृष्णा हाथी सिंह जी का वर्णन माननीय शास्त्री जी ने किया और जो वहाँ पर दुर्घटनाएं हुई, मैं समझता हूँ कि यह खुला चित्र है खुले तौर पर पर्चों और पोस्टर्स दीवारों पर लगे हैं जिस में न केवल पाकिस्तान जिन्दाबाद बल्कि भारत मुर्दाबाद के भी नारे छपे हुए हैं ।

ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं । वहाँ पर विधान सभा भवन के अन्दर विस्फोट हुए, लेकिन कोई आदमी नहीं पकड़ा गया । आखिर पकड़ा कैसे जाये, क्योंकि वहाँ के मंत्री-मण्डल के साथ इन पाकिस्तानी एलीमेंट्स की गहरी छनती है, वे आपस में इकट्ठे उठते-बैठते हैं । श्री मोहम्मद दीन बन्दे, वहाँ एक डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन के साथ एक रशीद नाम का व्यक्ति है, जो अभी उड़ी और पुँछ क्षेत्र में गया है, उस व्यक्ति को, हालाँकि उस के वारंट निकले हुए थे, अपने मकान के अन्दर रखा गया । उसको मोटर एक्सीडेंट के अन्दर चोट आई, तो उप-मंत्री की कार उस को वहाँ लेने के लिये गई और उस कार से लाकर उस को अस्पताल में दाखिल किया गया । इसी तरह से लतीफ, अजीज, इतनी कहानियाँ हैं इतने सारे षड्यन्त्र हैं जिनका वर्णन करके मैं अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता । आज इन मामलों की चाहे जितनी

मिसालें गृह मंत्री जी को दीजिये, मैं समझता हूँ कि उन के पास भी होंगी, मैं नहीं समझता कि उन की जुबान पर कौनसी मोहर लगी हुई है, अपनी कमजोरियों को वे स्वयं जानते हैं। उन के वहाँ जाने और बोलने के बाद वहाँ सारी चीजें जिस तरह से ठप्प पड़ गईं, मुझे पता नहीं कि उन का क्या राजनीतिक इतिहास है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। वहाँ की सरकार इस स्थिति को काबू में नहीं कर सकी है। केन्द्र की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को लेकर आगे आना चाहिये।

जहाँ तक केन्द्र की सरकार का सवाल है, उसकी नीति कुछ ऐसी विचित्र है कि वह अपने आप यह तय नहीं कर पा रही है कि काश्मीर के बारे में वह क्या नीति ले कर चले। मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो जायेगी और इसी तरह से स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि धारा 370 की आवाज मत उठाओ, यह अपने आप धीरे-धीरे घिसते-घिसते घिस जायेगी। मुझे इस सम्बन्ध में श्री गोपालस्वामी आर्यंगर के भाषण का एक हिस्सा आपको सुनाना है। जब धारा 370 लागू की जा रही थी और इस को काश्मीर के सम्बन्ध में लाने की बात की जा रही थी, उस समय श्री गोपालस्वामी आर्यंगर ने बोलते हुए कहा था—

"The discrimination is due to the special conditions of Kashmir. That particular State is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope."

श्री आर्यंगर ने कहा—

Mark the word 'hope....

"...of everybody here that, in due course even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States."

आगे जाकर फिर उन्होंने कहा—

"I would like to assure the House that we can only now establish an interim system."

मेरा यह कहना है कि 20 वर्ष बीतने को आ गये, अभी तक वह धारा घिसते-घिसते घिसी नहीं और आज हालत यह आ गई है कि हमारे देश की सुरक्षा और हमारी एकात्मता घिसते-घिसते घिस रही है—आखिर कब उस का समय आयेगा। आज हमारे माननीय कुशक वाकुल जी जैसे राष्ट्रभक्त और श्रीमान बख्शी गुलाम मुहम्मद जी जैसे देशभक्तों को दुखी होकर इस प्रकार की स्थिति में पड़ जाना पड़ा कि वहाँ वे अपने को पराया महसूस करें और पाकिस्तानी एजेंट आज वहाँ पर सब कुछ बन कर बैठे हुए हैं, यहाँ का गया हुआ माल-खजाना खा रहे हैं और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। यह कैसी विचित्र स्थिति है। मैं यह समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों को दृष्टि में रख कर हमें धारा 370 को समाप्त करना चाहिये और हमें अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये।

कुछ मित्रों ने इस प्रकार की बात कही है कि वहाँ चुनाव हो गया है—सवाल यह नहीं है, सवाल तो सरकार के मन और मस्तिष्क की स्पष्टता का है। आज जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर बना हुआ है—अलगाव का—हमारे जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक वहाँ पर गये, परिस्थितियों ने उन को विवश किया, आपके लोगों ने कहा कि आप इस वातावरण की शांति के लिये कुछ प्रयत्न करें—सादिक साहब ने स्वयं कहा कि आपने बहुत ही ठीक प्रकार से तमाम बातों को कहा है, लेकिन उन्हीं के चारों तरफ के लोगों ने, जो पाकिस्तान के हाथ में खिलौना हैं, उन्होंने उस को इस प्रकार की रंगत दी कि वहाँ पर होवा खड़ा कर दिया, साम्प्रदायिकता पैदा हुई है; वहाँ के मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। कृपा कर के बताइये—धर्म परिवर्तन की घटनायें हिन्दुओं की ओर से कितनी हुईं और अल्पसंख्यकों की ओर से कितनी हुईं। वहाँ पर इस प्रकार का जो प्रो-पाकिस्तानी एलीमेंट है, उस ने इस प्रकार से साम्प्रदायिक मामलों को भड़काया।

[श्री य० व० शर्मा]

इसी स्थिति से सम्बन्धित एक बात और कहना चाहता हूँ—वहाँ पर जम्मू और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं—नौकरियों के मामलों में और आर्थिक विकास के मामलों में वहाँ की जनता के साथ सौतेली मां का-सा व्यवहार किया जा रहा है। आज उस सरकार की अलगाव की बात को समाप्त नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर शिव सेना और दूसरी सेनाओं की चर्चा रोख हो जाती है। मैं यह समझता हूँ कि अगर यह धारा वहाँ पर कायम रही तो इस प्रकार के अलगाव के बीज जो सरकार अपनी नीति के कारण वहाँ पर बो रही है, उस के बड़े भयंकर परिणाम होंगे। क्यों नहीं काश्मीर को बाकी राज्यों के समान स्तर पर आने दिया जाता, क्यों नहीं वहाँ के लोगों को बाकी राज्यों के लोगों के साथ एकरस और एकरूप होने की स्थिति में लाया जाता, अगर सरकार उस को समाप्त करे—और सरकार तब समाप्त कर सकेगी जब काश्मीर के सम्बन्ध में उस की नीति और दृष्टि स्पष्ट हो जायेगी—लेकिन सरकार के मन में पाप है, मैं समझता हूँ कि सरकार अमरीका या रूस आदि इस प्रकार की विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण इस प्रकार के पाप को ले कर बैठी है, जो काश्मीर के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस लिये वहाँ पर जिन कठपुतलियों को कायम करके बैठाया हुआ है, उन को समाप्त करना होगा, वहाँ पर राष्ट्रपति राज्य लागू किया जाये, धारा 370 को समाप्त किया जाये, सारे राज्य के अन्दर—चाहे जम्मू हो या लद्दाख—आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाये और जम्मू-काश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के स्तर पर लाया जाये।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI (Bilhaur) : Sir, I would like to thank Shri Prakash Vir Shastri for giving this august House... (Interruptions).

AN HON. MEMBER : in Hindi please.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all right. It is for her to choose in which language she would like to speak.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I would like to thank Shri Prakash Vir Shastri for focussing the attention of this august House on a matter of vital importance because Kashmir enjoys a very peculiar position and especially because Kashmir happens to possess the misfortune of being looked upon by greedy eyes by two very hostile neighbours—China and Pakistan, also because Kashmir had been the arena of two hostile aggressions. Therefore, I would request this House to study this matter in the most dispassionate manner, to have a clear perspective and, at the same time, not to be carried away by emotions.

If my hon. friend thinks that the only remedy for this lies in the repeal of Article 370, I would like to contradict him and tell him that while he wants the repeal of Art. 370, at the same time he wants President's proclamation. President's proclamation can only be introduced by invoking Article 356. Therefore, I would like to ask him : was it not under Mr. Sadiq's Ministry, was it not under Mr. Sadiq's inspiration that this Art. 356 is now in a position to be enforced in Kashmir ? And we should be grateful to this Ministry of Mr. Sadiq for bringing Kashmir under the purview where this article can be extended to Kashmir also. I would like to differ from Mr. Prakash Vir Shastri on this basic constitutional aspect. While enforcing Art. 356 and enforcing President's Proclamation, I would like to draw his attention to two matters of vital importance. First it says that the Governor's report should be such and, secondly, that the situation otherwise should be such that this Proclamation could be introduced. I would like to ask him as to what the present position in Kashmir is. Has a report been submitted by the Governor advocating that there should be President's Proclamation ? To this the reply is a categorical 'No'. Secondly, what is the situation otherwise prevailing in Kashmir ? There is a democratic machinery there, which is functioning

in a democratic manner. Not even the Opposition there has ever, any time, said that it has a doubt in the majority of the present Ministry. I would like to ask : then what is the reason? If there is a democratic machinery functioning, a properly constituted, elected Government functioning, why should the President's Proclamation be imposed there? If you want to compare it with West Bengal, I would very clearly say that the situations are entirely different. What has happened in West Bengal has made us hang our heads down in shame. Irrespective of our Party affiliations and irrespective of whatever ideals we may have, what has happened in West Bengal, I hope, we shall all agree, should not be repeated in any other State whether it is Congress Party or any other Party in power there. In West Bengal there was no Government, there was no administration, there was nothing.

So far as comparison with Haryana is concerned, in Haryana the Governor's report was there.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Let her confine herself to Kashmir.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Otherwise, she will have nothing to say tomorrow.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : I do not intend to say anything tomorrow.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Let her choose between Ayub and Mao. One side there is Ayub and on the other side there is Mao. If Mao's slogans are bad, Ayub's slogans are equally bad. He has been a student in fact a teacher of constitutional history. Unless I sit down, how can he get up and interrupt?

I was referring to Haryana. I would like humbly to place before the House the situation in Haryana. The situation in Haryana is different from that in Kashmir. The Governor had reported that crossing of the floor by Members was not merely a disease but it had assumed an endemic form and it had become infectious. (*Interruptions*) I had never interrupted any of my friends. May I expect the same courtesy from them?

MR. DEPUTY-SPEAKER : She may, ignore the interruptions from the other side.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : It is difficult to ignore them because I have great respect for my hon. friends in the Opposition....

SHRI KANWAR LAL GÚPTA (Delhi Sadar) : Shri Piloo Mody cannot be ignored.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I was not talking of him. He is too much present in the House. I was talking of interruptions.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : I would like them to give me the same courtesy which I had shown to them. That is the least that I expect of any Member there.

In Haryana, according to the Governor's report, the people had come to power by means which were not very honourable. So, the comparison with Haryana was not proper. In Haryana, there was no question of any stability of government and any stability of administration. So, putting Haryana and Kashmir on the same footing is not a very correct thing to do. May I ask why there is this sudden demand for a Presidential Proclamation like a bolt from the blue? Why are the people who are professed democrats here, who have fought the elections on democratic basis advocating this Presidential Proclamation? In Bihar when similar incidents happened in Ranchi and more than 150 lives were lost there in 48 hours, there was no cry for such proclamation. Again, at Sursand, more than a hundred lives were lost in a couple of hours; no such cry was raised on that occasion. Was it because the Opposition Ministry was in power there? Was it because there was no Congress Ministry there in power and people dare not judge their own Ministry by the same measure or the same yardstick by which they want to measure us? I would expect the same yard-stick to be applied by them everywhere. We are mature people here, and let us not forget today that we are the biggest democracy in the world; let us not forget today that we have the most glorious civilisation as our heritage; let us not forget today that we are one of the most mature and

[Shrimati Sushila Rohatgi]

civilised countries, which have come up to the standard high democratic functioning.

While Shri Prakash Vir Shastri has focussed the attention of this House on this important matter and it must receive the attention of this House and that of the Home Minister, at the same time, I would appeal to him that he must not create an alarmist tendency, especially in a vulnerable place like this, because if he does so, the morale of the people will suffer and when the morale suffers, that will be the first below on our arsenal of defence. Therefore, I would request him to withdraw this motion.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) :

जनाब डिप्टी स्पोक, कश्मीर पर मुझ से पहले कुछ चन्द्र एक आनरेबल मॅम्बर्स ने अपने खयालात का इजहार किया लेकिन एक चीज पहले ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ एक गलतफहमी दूर करने के लिए और वह यह कि कश्मीर में बदकिस्मती से जो 7 जून से सितम्बर तक हुआ तो कश्मीर को उसी माइजरिटो और मेजरिटो के पार्ड-स्ट्रिक से न नाचिये क्योंकि कश्मीर को मेजरिटो और कश्मीर को माइजरिटो हजारहा साल से इकट्ठा रहता आई है। वह सैकुलर रही है और आगे भी सैकुलर रहेगी।

They have lived like that and they can live like that till eternity

वहाँ जो कुछ हुआ, प्रकाशवीर शास्त्री जो ने या मेरे और दोस्तों ने कहा, कम्युनलिज्म वहाँ पर मुसलमान ने नहीं किया, हिन्दू ने नहीं किया, मुसलमान ने हिन्दू पर हाथ नहीं उठाया और हिन्दू ने मुसलमान पर हाथ नहीं उठाया। यह कम्युनलिज्म वाली बिलकुल गलत बात है और मैं जोरशोर से इसको तर्दोद करना हूँ। अगर वहाँ कोई आदमी मरा है तो वह पुलिस की गोली से मरा है, लाठीचार्ज से मरा है। वह पुलिस की फायरिंग से मरा है। कश्मीर सैकुलर रही है, सैकुलर है और वह सैकुलर

रहेगा। कश्मीर ने तमाम कंट्रोवर्सिज के बगैर अपना नाम हिन्दुस्तान के साथ जोड़ा है, वह आज जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा यह मैं आप को बतलाना चाहता हूँ। बाकी कश्मीर के बारे में कंट्रोवर्सि रहने के कई कारण हो सकते हैं। अब किसी दोस्त का यह सुझाव है कि फलानी दफा को उड़ा दो सब ठीक हो जायगा। मेरा अपना यह खयाल है, मैं ईमानदारी से यह कहना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने जनाब से पहले मांगा था वक्त। कश्मीर की बदकिस्मती से मौजूदा गवर्नमेंट जो है, मैं किसी नाराजगी या किसी रेंकर की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि लाल बहादुर जो ने जब मौजूदा गवर्नमेंट को इंस्टाल किया फरवरी 64 में तब भी यह रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे इनके साथ पापुलर ओपीनियन नहीं थी और 67 का एलैक्शन जब आया, तीन साल गुजरे 67 में जब एलैक्शन आया और इस एलैक्शन के बारे में लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई थी कि यह एलैक्शंस फ्री होंगे, इम्पारशियल तरीके से होंगे और जो भी गवर्नमेंट पावर में आयेगी यह लोगों की गवर्नमेंट होगी। वह कश्मीर की खिदमत करेगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभायेगी लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या? एलैक्शंस से पहले वहाँ जिसका तजकिरा मेरे फाजिल दोस्त शास्त्री जी ने किया 10,000 होम-गाइड्स दिसम्बर से ही वहाँ पर उन्होंने फंक्शन करना शुरू किया। उसके मुताल्लिक मैं ने आनरेबल होम मिनिस्टर को एक लम्बा चीड़ा खत लिखा कि इस में यह यह हो रहा है और आप इयं जरा तवज्जह दीजिये।

They are breaking meeting of opposition parties.

हम खुद मीटिंग नहीं कर सकते। जहाँ भी हम मीटिंग करते हैं वहाँ वह ब्रेक करते हैं और इस सिलसिले में कितने ही हमारे आदमियों को एक, दो को नहीं बल्कि सैकड़ों आदमियों को जकदी कर दिया। मैंने खुद मि० चह्माण को लिखा। उसके बाद एलैक्शन कमिशन ने ऐनाऊंस किया ला मिनिस्टर ने यहाँ पालिया-मेंट में ऐनाऊंस किया कि जम्म व काश्मीर में

एलैक्शंस होंगे। जम्मू में एलैक्शंस रैस्ट आफ दी कंट्री के साथ होंगे और कश्मीर के हालात सामने रख कर वहां पर एंड ऑफ दी मार्च में होंगे क्योंकि यही शैड्यूल पहले भी रहा है। लेकिन हुआ क्या ? इस बारे में एलैक्शन कमिशन का नोटिफिकेशन है लेकिन रूलिंग पार्टी का मैं उन को कोई नाम नहीं देता, जिस तरीके से मैं ने आप से कहा कि रूलिंग पार्टी ने फौरी तौर पर, वह कोई पसन्द नहीं या लेकिन उन्होंने ऐनाऊंस किया, एलैक्शन कमिशन ने ऐनाऊंस किया कि कश्मीर के लिए 21 मार्च और जम्मू के लिए 19 फरवरी होगी पंजाब के साथ-साथ। फौरी तौर पर बदल गये हम ने रिप्रेजेंटेशन किया और बजाय मार्च के अप्रैल कर दिया और जम्मू, कश्मीर में एक साथ कर दिया। एलैक्शन कमिशन ने फंसला क्या दिया ? नहीं कश्मीर में भी 21 फरवरी को ही चुनाव होगा जबकि कश्मीर में 3,4,5 और 6-6 फुट बरफ जमी हुई थी। पहली तो यह बात है फिर उसके बाद 21 जनवरी आई नामिनेशन पेपर्स दाखिल करने थे और सब ने नामिनेशन पेपर्स दाखिल कर दिये। हम ने भी और दूसरी ओर अपोजीशन पार्टीज ने अपने नामिनेशन पेपर्स दाखिल किये और मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों के 141 नामिनेशन पेपर्स फिल्मजियस्ट ग्राउन्ड्स पर रिजैक्ट हुए और जिसे कि छुद इलैक्शन कमिशन मानता है।

Not a single nomination paper of the ruling party was rejected रियल पोलीशन यह है Then we again approached President, the hon. Prime Minister, the Home Minister and other Central Ministres, put all these facts before them.

इस पर हम ने मतालबा किया कि इन होलसेल रिजैक्शंस की बजह और मौसम की खराबी की बजह से एलैक्शन को ऐनल कर दिया जाय या फिर पोस्टपोन ही कर दिया जाय लेकिन न तो उसे ऐनल किया गया और न ही पोस्ट पोन किया गया। मैंने चह्वाण साहब को खत

L88LSS/67-10 Δ

लिखा कि साहब कम से कम यह तबक्को नहीं हो सकती एक ऐसी गवर्नमेंट से और एक ऐसी सरकार से जिसने हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अपना हर एक हक न्यौछावर किया हो। उन से यह तबक्को नहीं हो सकती। और चह्वाण साहब ने मुझे खत लिखा। मैं वह खत पढ़ कर सुनाता हूं :

"I have your letter No. dated 7th January I am forwarding a copy of this letter to Sadiq Saheb, with a request that he should look into your complaints personally and satisfy himself that nothing wrong or improper is done. I am very keen that the elections in Jammu and Kashmir, as in the rest of the country, should not only be fair, but should also appear to be so, and that nothing should be done that can be regarded as at all unfair and improper."

17 HRS.

यह है चह्वाण साहब का खत। अब इस से और एक हिम्मत हुई हमें कि एलैक्शन फेयर और इम्पाशियल होंगे। लेकिन जनाब हुआ क्या ? रिजैक्शंस हुए। 26 आदमी असेम्बली में अनकन्टेस्टेड आ गए स्ट्रेटअवे लिहाजा 26 की स्ट्रेंथ बन गई और फिर उस के बाद बाकी जो हुआ वह सब को मालूम है। दीज आर आल ओपेन सीक्रेट्स।

These are all open secrets. बैलट बाक्सोज, आये, टूटे और लिड्स के बगैर, सील के बगैर, बैलट पेपर एकाउंट के बगैर। हम ने एतराज किया। लेकिन no body just did any thing or cared.

कहा कि ठीक है काउंट किया जावे। एलैक्शन कमीशन ने दो आदमी यहां से भेजे काश्मीर में इसे देखने के लिए with no instructions. वह बिलकुल खड़े रहे भूत की तरह। वह देखते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे ? और पार्टीकुलर कांस्टीट्यूएन्सी में क्या हुआ, 550 टोटल स्ट्रेंथ है उस बूथ की लेकिन उस बक्से में से

[श्री मुलान मुहम्मद बक्शी]

1185 बैलट्स निकले। यह हुआ।
(ब्यवधान) इस पर भी कुछ नहीं हुआ। हम डाक्टर कर्ण सिंह जो उस वक्त वहाँ के गवर्नर थे, उन से भी मिले, सब से मिले, वावेली किया, राष्ट्रपति से मिले लेकिन आखिर जो हम को हुक्म हुआ कि कानून इजाजत नहीं देता। हम ऐनल तो नहीं करेंगे क्योंकि बाहर दुनिया में क्या कहा जायगा? हम ने कहा कि बाहर दुनिया में हमारी तो नाक कट गई। इंडिया के मुतालिक यह कहा जाता था कि यहाँ एलेक्शन फेयर और इम्पाशियल होते हैं। चुनावे हमारे शिव कुमार सेन सूडान और ईजिप्ट में एलेक्शन कराने के लिए गए और यहाँ यह हो रहा है। खुद सुन्दरम् ने यह कहा है :

"that the nomination papers of a large number of opposition candidates were rejected on flimsy grounds is serious."

और फिर वह कहते हैं :

"That difference in law is not satisfactory, and I intend recommending to the State Government that the State election law should be brought in line with the general election law on this point as soon as possible."

यह सुन्दरम् कहते हैं कि मामला सीरिअस है। हॉरिडिदायत दो कि जाओ एलेक्शन पेटोशन करो। हम ने कहा कि बहुत अच्छा। जब और कुछ नहीं होता है तो यही एक ही रेमेडी है कि एलेक्शन पेटोशन करो। That is the law of the country. और हम उसके सामने झुके। तो जनाब वह भी माजरा सुन लीजिए कि 57 एलेक्शन पेटोशंस हैं काश्मीर की। आन्ध्र प्रदेश में 12 थीं और बारह डिस्पोज हो गई। हरयाना में 13 थीं और उसमें से 12 का फंसला अभी तक हो चुका है। महाराष्ट्र में 21 थीं, 20 का फंसला हो चुका। मैसूर में 21 थीं, 13 का फंसला हुआ है जब कि जम्मू और काश्मीर में 57 एलेक्शंस थीं और खुदा के फजल से एक का फंसला हुआ है। रीअल

स्टोरी पर आईए। ट्रिब्यूनल बनता है। सुन्दरम् ने कहा—ला बदल दो।

Bring it on a par with the rest of the country—as early as February 67.

असेम्बली मिली मार्च में। उस में ला पास नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ? ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया अन्डर दि ओल्ड ला। ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया। एक फंसला दिया। यानी उसका शिड्यूल था वह 26 के फंसले देने वाला था इन दि मंथ आफ सितम्बर।

(ब्यवधान) तो फिर क्या हुआ? 26 जो अनकन्टेस्टेड रिटर्न्स थे इन का फंसला होता सितम्बर तक। काश्मीर असेम्बली में उनका पता लग गया कि एक अनसीट हो गया।

Because of uncontested return rejection of nomination paper.

25 और होंगे। तो उन्होंने एक दिन में ला बदल दिया और वह ला भी एक दिन में असेम्बली बैठो, और उसे बदल दिया। 9 सितम्बर को बदला और 10 सितम्बर को असेंट ले ली गवर्नर से। 11 को लागू कर दिया और एलेक्शन ट्रिब्यूनल जो सरकार ने मुकर्रर किया था वह अदालत में बैठा हुआ था एलेक्शन पेटोशन सुनने के लिए, चपरासी गया और उसको कहा कि

"You are no more an election tribunal; please go. यह 11 को हुआ और 11 को जब यह हुआ, मैं पहुँचा दौड़ते दौड़ते फिर चह्नाण साहब के पास। आखिर कहां जायें? हाकिम तो यही हैं। हम तो इन्हीं से बतायेंगे, आगे तफतीश इनका काम है। मैं फिर आया। मैंने लम्बा चौड़ा खत लिखा और उन को बता दिया कि यह ला ऐसे पास हुआ और क्या-क्या हुआ इस तरह एक दिन में। एलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म हो गया। मैंने कहा कि ऐड हाक जजेज जल्द से जल्द मुकर्रर कीजिए। इन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। यह बात हुई शायद 14 सितम्बर को। और आज सितम्बर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवम्बर भी गया, आज आखीरी तारीख है नवम्बर की। नी महीने

हो गए हमारी एलेक्शन पेटोशन के। 57 एलेक्शन पेटोशंस में से 1 का फैसला हुआ है और खुदा ने चाहा अगर यही स्पीड रही तो कम से कम 10 साल इन को चाहिए यह फैसले करने के लिए हालांकि कानून है कि विदिन सिक्स मन्यम् होना चाहिए। महाराष्ट्र में 21 में 20 का फैसला हो गया। हरयाना में 15 में से 12 का फैसला हो गया। बाई एलेक्शन भी हो गए। लेकिन काश्मीर जिस को कि कहा जाता है कि स्पेशल सबजेक्ट है, 370 है, 380 है, 390 है, मुझे मालूम नहीं और कौन-कौन से सबजेक्ट्स लागू हैं लेकिन यह क्या है कि आज तक इस वक्त तक कोई ऐड हाक जज मुकर्रर नहीं हुआ? अब हाईकोर्ट में वहां तीन आदमी मुएतकिल हैं।

They are fully occupied with their own work वह नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा।

लेकिन मैं राष्ट्रपति राज्य के मुताल्लिक कहूँ तो उन्हें नामंजूर होगी बात। मैं एक बात कहूँगा कि जो, मेरा खयाल है कि उन्हें पसन्द आयेगी। मैं उन को यह कहूँगा कि यह माइनारिटी गवर्नमेंट जो है जो इस तरह बनी है और जिस के खिलाफ इतने पेटोशंस हैं, इसको डिसमिस कीजिए, यह भी आप नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है नहीं मानेंगे आप। काश्मीर स्पेशल सबजेक्ट है। तो फिर मैं अर्ज करूँगा आप से कि आज नौ महीने हो गए हैं, अब दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च चार महीने हैं, मामूली सा सजेसन आप से अर्ज करता हूँ, पाजिटिव सजेसन है, इस चार महीने में इन सब पेटोशंस का फैसला करा दीजिए।

And let there be fresh elections in April 68. यह मेरा सजेसन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जजेज को एप्वाइन्ट करें, जो कि इन कैसेज को जल्द से जल्द डिस्पोज करें। मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ और एक्सट्रीम में नहीं जाऊँगा—यह एक सुझाव है, मेहरबानी कर के इमीडियेट स्टैप्स लीजिये, 141 कैसेज को डिसाइड कराइये, खास तौर से 41 कैसेज असेम्बली के हैं जिन को जजेज को मुकर्रर

करके डिसाइड कराइये। अगर ये कैसेज मार्च के आखिर तक डिसाइड हो जायें तो फ्रेश इलेक्शन्स अप्रैल में हो सकते हैं। फ्रेश इलेक्शन्स से मेरा मतलब बाईइलेक्शन से है।

दूसरी बात यहां पर काश्मीर को दी जाने वाली सहायता के मुताल्लिक कहा गया है। काश्मीर आपका एक गरीब साथी है—जहां बम्बई और कलकत्ता जैसे आपके अमीर साथी हैं, वहां काश्मीर जैसा एक छोटा और गरीब साथी भी है, इस लिये सहायता तो उसको देनी ही पड़ेगी। मैं आपकी इत्तला के तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ कि 1947 से मार्च, 1964 तक टोटल ग्रान्ट्स और लोनज जो काश्मीर को मिले—वह ये तकरीबन 72 करोड़ रुपये, लेकिन 1964 से 1966 के आखिर तक जो नई सरकार को मिले—वह ये 70 करोड़ रुपये, यानी दो साल में उन को 70 करोड़ रुपया दिया गया—मैं चाहता हूँ कि आप इस को जरा देखभाल कीजिये। मैं यह जो फिर्स आपके सामने पढ़ रहा हूँ—ये मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट से कोट कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी फिर्स नहीं है, बल्कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट से जो फिगज मेरे पास आई है, उन में से बता रहा हूँ। काश्मीर पर थोड़ा रहम खाइये। पाटोदिया जी ने एक बड़ी ही कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच की बात कही है—लोगों को अपने साथ रखिये, लेकिन उन को काम दीजिये, वहां पर काम धन्धों का एक्सपेन्शन होना चाहिये, इण्डस्ट्रियल डवेलप-मेंट होना चाहिये, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिये—लेकिन होता क्या है? जैनेरल एडमिनिस्ट्रेशन पर 1962-63 में 61 लाख रुपये खर्च हुआ, लेकिन आज चार साल बाद वह बढ़ कर 1 करोड़ 10 लाख हो गया—यह एक्सपेन्शन वहां पर हुआ है। पुलिस पर 1963-64 में एक करोड़ रुपये खर्च था, लेकिन अब वह बढ़ कर पोने तीन करोड़ हो गया है—यह एक्सपेन्शन हुआ है। ये फिर्स मैं काश्मीर बजट से पेश कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज के बजट में हम उस वक्त 2 करोड़ 49 लाख

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

रुपये, तकरीबन ढाई करोड़ रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब उस पर 49 लाख रुपये खर्च हुए हैं—यानी जो डवेलपमेंट की चीज थी, उनको रोक दिया गया है। मि० डांगे यहां बैठे थे—वह लेबर के मामले में वहां गये थे। हमारी सिल्क फैक्ट्री में जहां चार हजार आदमी काम करते थे, वहां अब पांच सौ से भी ज्यादा नहीं है। कोकूनज 60 हजार मन पैदा होती थी, वहां अब 10-12 हजार मन पैदा होती है—7-8 महीने से वे लोग बेकार हैं। इस लिये जनाब, मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों पर तबज्जह दी जाय।

दूसरी बात में होमगार्ड्स और फील्ड सर्वे आरगेनिजेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। यहां पर अभी एफ० एस० ए० का तज्जिकरा हुआ, जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होता है। अगर आप उनको डिस्मिस करेंगे...

महन्त विग्निजय नाथ (गोरखपुर) : वे हिन्दू हैं या मुसलमान ?

बख्शी गुलाम मुहम्मद : हिन्दू-मुसलमान सब हैं। अब अगर इन 10 हजार आदमियों को आप डिस्मिस करेंगे तो शायद एक नई प्राबल्म एम्प्लायमेंट की खड़ी हो जायगी। लेकिन यह बात ठीक है—कि इनके अन्दर जो एन्टी-नेशनल, एन्टी-सोशल एलीमेंट भरे हुए हैं, इन को वीड-आउट किया जाय और जो बाकी बचते हैं, उन को एबजाव कर लिया जाये और इन को आप थियेटर-कमाण्डर को हैण्डओवर कर दें। आप उनको कह दीजिये कि सेन्टर इस में ग्रान्ट देता है, 90 फीसदी तक और बार्डर डिफेन्स के लिये उन को रखा गया है और उस के बाद उन को चाइना बार्डर और पाकिस्तान बार्डर पर लगा दीजिये, क्या जरूरी है कि उन को श्रीनगर या अनन्तनाग या बारामुला में ही लगाया जाये। वहां उन का क्या काम है ? इस लिये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह से डिस्मिस करना मुश्किल होगा, लिहाजा आप इतनी कृपा कीजिये कि जिस काम के लिये उनको भरती किया गया है, उन को उस काम

पर लगाया जाय और स्ट्रेट-अवे उन से वह काम लिया जाय। उनको लद्दाख भेज दीजिये, चुशूल भेज दीजिये, कारगिल भेज दीजिये—बार्डर पर लगा दीजिये।

यहां पर फूड के सिलसिले में तज्जिकरा हुआ—वाकई एलामिग पोजीशन थी। जब सैलाब के साल में यानी 1957 से 1959 में 60 हजार टन से 62 हजार टन से ज्यादा गल्ला नहीं गया—हर किस्म का गल्ला—राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, व्हीट वगैरह, लेकिन 1965-66 में मेरे एक सवाल के जवाब में, जो कि मुझे कल ही मिला है, बताया गया है कि 3 साल में 5 लाख 58 हजार टन गल्ला गया है—मैं चाहता हूँ कि इस की देखभाल की जाये कि ऐसा क्यों हुआ है।

यहां पर किसी दोस्त ने शायद ऐसा कहा कि काश्मीर को सस्ता गल्ला दिया जाता है। मैं इस हाउस की इतिला के लिये अर्ज करना चाहता हूँ कि काश्मीर को भी उसी कीमत पर गल्ला दिया जाता है, जिस कीमत पर दूसरों को मिलता है। हां, काश्मीर गवर्नमेंट उस में अपनी तरफ से सबसिडी देती है, उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया सबसीडाइज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया 1957-58 तक करती थी, लेकिन अब काश्मीर गवर्नमेंट कर रही है। हां यह बात जरूर है कि काश्मीर गवर्नमेंट पहले टू दी टयून आफ 1,25,000, 1,75,000 और ढाई लाख तक करती थी, लेकिन अब यह हो गया है कि 8 करोड़ रुपये तक किया जा रहा है—इस लिये मेरा खयाल है कि इस तरफ भी तबज्जह देने की जरूरत है।

तीसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाब सादिक ने अपने पालिसी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं डेमाक्रेसी में बिलीव करता हूँ। यकीनन अगर मेरे जमाने में एक बार भी गोली चली, तो मैं उसी वक्त कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन यह कुर्सी जनाब इतनी प्यारी है कि कोई उसको नहीं छोड़ता। अब

आप देख लीजिये कि कितनी बार वहां पर गोली चली। इस सरकार से हम को तीन चीजें मिली हैं — 1965 में इन्डो-पाकिस्तान कान्फ्लिक्ट हुआ—बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला। हमारे चह्वाण साहब उस वक्त 3 अगस्त को श्रीनगर में थे—उन्होंने उस वक्त कहा—

“There is no fear of infiltration and we have sealed the borders”. On the 8th of August, on this very hon. House, Shri Nanda announced that 12,000 infiltrations have reached Srinagar and they have surrounded Srinagar.

में इसकी डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अवाल पालिसी आफ़ लिब्रलाइजेशन का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जमाने में एक बार भी गोली नहीं चली—1953 से लेकर 1963 तक एक बार भी लोगों पर गोली नहीं चली, एक भी स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन 1964 से ये सब होना शुरू हो गया—अब, आप कह दीजिये कि यह सब तुम करा रहे हो। बरूणी फोबिया कह दीजिये।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि 1965 में पाकिस्तान-इंडिया कान्फ्लिक्ट का तोहफ़ा मिला, 1966 में जम्मू स्टूडेंट्स पर फाईरिंग और किलिंग हुई और 1967 में काश्मीर के हिन्दू और मुसलमान दोनों पर फाईरिंग हुआ—वहां पर दफा 144 को लागू किया गया। दफा 144 तो जनाब काश्मीर के आइने का, किताब का एक स्टेचूट बन गया है—

It is perpetual 144 since 1965 up to this time.

और मैं आपकी आगाही के लिये यह भी अर्ज कर दूँ कि पिछले इलेक्शन के दौरान भी दफा 144 को नहीं उठाया गया। हम लोग इजाजत लेकर जल्से करते थे, अगर इजाजत मिल जाती थी तो जल्सा करते थे, अगर इजाजत नहीं मिलती थी तो नहीं कर सकते थे।

It has become perpetual.

करफ्यू के सिलसिले में भी अर्ज कर दूँ। यहां बंगाल की हालत यह है कि अगर 24 घण्टे

का भी करफ्यू लगता है तो इतना शोर होता है, लेकिन वहां पांच दिन तक तो करफ्यू के नीचे बिलकुल बन्द ही रहा और अभी तक भी नाइट-करफ्यू चलता है—यह हालत आज वहां की है। आप यह कहेंगे कि मैं वहां की गर्बन-मेंट की डिफिकल्टीज को जानता हूँ एक दोस्त ने यहां कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति राज्य का मतालवा करने से अगर हम राष्ट्रपति राज्य वहां पर लागू करेंगे तो पाकिस्तान के हाथ में हम एक हैंडिल देंगे तो मेरा कहना है कि हैंडिल तो जनाबवाला हम ने उसी दिन पाकिस्तान को दे दिया जिस दिन कि यह 141 नामिनेशन फोर्म्स रिजैक्ट कर दिये और तब से वह बराबर दिया जा रहा है। मुझे फिक्र है कि डेमोक्रेसी का क्या होगा? बाकी अब चूँकि वक्त नहीं है इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल यह एक नक्शा था जो मैंने आप के सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ मोडरेट और प्रैक्टिकल सजेशंस दिये हैं और उन को एक्सेप्ट करने में आप को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए या फिर यह कहिये कि वह आप की उस फारसी के शायर जैसी हालत है जिसने यह लिखा है:

“उम्मे बायद कि यार आयद बकनार”।
तुम भी रहो हजार साल और यह सिलसिला भी चलता रहे हजार साल। आप ने यह नहीं करना है और न यह हमें हासिल होगा।

इसलिए मैं आखिर में बस यही अर्ज कर के खत्म करूँगा कि कश्मीर हिन्दुस्तान के साथ है, कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के हिन्दू, जम्मू के हिन्दू व सिख और लद्दाख के बौद्ध सब हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह उन तमाम चीजों के बावजूद हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तानी रहे हैं और आगे वह हिन्दुस्तानी रहने वाले हैं और वह उस से दूर नहीं जायेंगे।

شری بخشى غلام محمد (شری)

نگر): جناب ڈپٹی اسپیکر—کشمیر پر مجھ

[شری بخشی غلام محمد]

سے پہلے کچھ چند ایک آئریبل میمبرس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن ایک چیز پہلے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غلط فہمی دور کرنے کے لئے اور وہ یہ ہے، کہ کشمیر میں بد قسمتی سے جو ۷ جون سے ستمبر تک ہوا تو کشمیر کو اسی مائنٹرائٹی اور مجارٹی کے یارڈاسٹک سے نہ ناپئے کیونکہ کشمیر کی مجارٹی اور کشمیر کی مائنٹرائٹی ہزارہا سال سے اکٹھا رہتی آئی ہے۔ وہ سیکولر رہی ہے۔ ہے اور آگے بھی سیکولر رہیگی۔

They have lived like that and they can live like that till eternity.

وہاں جو کچھ ہوا پرکاش ویر شاستری جی نے یا میرے اور دوستوں نے کہا کمیونلزم وہاں پر مسلمان نے نہیں کیا ہندو نے نہیں کیا مسلمان نے ہندو پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور ہندو نے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کمیونلزم والی بالکل غلط بات ہے اور میں زور شور سے اس کی تردید کرتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی آدمی مرا ہے تو وہ پولیس کی گولی سے مرا ہے لائٹی چارج سے مرا ہے۔ وہ پولیس کی فائرنگ سے مرا ہے۔ کشمیر سیکولر رہا ہے۔ سیکولر ہے اور سیکولر رہیگا۔ کشمیر نے تمام کنٹروورسز کے بغیر اپنا نام ہندوستان کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ آج جڑا ہے اور

آگے بھی جڑا رہیگا یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ باقی کشمیر کے بارے میں کنٹروورسی رہنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں۔ اب کسی دوست کا یہ سچھاؤ ہے کہ فلانی دفعہ کو اڑا دو سب ٹھیک ہو جائیگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے۔ میں ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں نے جناب سے پہلے مانگا تھا وقت۔ کشمیر کی بد قسمتی سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے میں کسی ناراضگی یا کسی دینکر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لال بہادر جی نے جب موجودہ گورنمنٹ کو انسٹال کیا فروری ۱۹۶۳ میں تب بھی وہ ریپریزنٹٹیو نہیں تھے ان کے ساتھ پاپلر اوپینشن نہیں تھی اور ۶۷ کا ایلکشن جب آیا۔ تین سال گزرے اور ۶۷ میں جب ایلکشن کے بارے میں لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی تھیں کہ یہ ایلکشن فری ہونگے اسپارشل طریقے سے ہونگے اور جو بھی گورنمنٹ پاور میں آئیگی وہ لوگوں کی گورنمنٹ ہوگی۔ وہ کشمیر کی خدمت کریگی اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیگی لیکن بد قسمتی سے ہوا کیا۔ ایلکشن سے پہلے وہاں جس کا تذکرہ میرے فاضل دوست شاستری جی نے کیا ۱۰۰۰۰ ہوم گارڈس نے دسمبر سے ہی وہاں پر انہوں نے فنکشن کرنا شروع کیا۔ اس کے متعلق میں نے آئریبل ہوم منسٹر کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا کہ اس میں یہ ہو

رہا ہے اور آپ ادھر اور ذرا توجہ
دیجئے۔

They are breaking meetings of Opposition parties.

ہم خود میٹنگ نہیں کر سکتے۔
جہاں بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں وہاں
وہ بریک کرتے ہیں اور اس سلسلے میں
کتنے ہی ہمارے آدمیوں کو۔ ایک
دو کو نہیں بلکہ سینکڑوں آدمیوں کو
زخمی کر دیا۔ میں نے خود منسٹر
کو لکھا۔ چوہان کو لکھا۔
اس کے بعد ایک ایلکشن کمیشن
نے ایناؤنس کیا لا منسٹر نے
یہاں و پارلیامنٹ میں ایناؤنس کیا کہ
جموں و کشمیر میں ایلکشنس ہونگے۔

جموں میں ایلکشنس ریٹ آف دی
کنٹری کے ساتھ ہونگے اور کشمیر کے
حالات سامنے رکھ کر وہاں پر اینڈ آف
دی مارچ میں ہونگے کیونکہ یہی
شدیول پہلے بھی رہا ہے۔ لیکن ہوا
کیا۔ اس بارے میں ایلکشن کمیشن
کا نوٹیفکیشن ہے لیکن وہ رولنگ پارٹی
کا میں ان کو کوئی نام نہیں دیتا
جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا
رولنگ پارٹی نے فوری طور پر وہ کوئی
پسند نہیں تھا لیکن انہوں نے ایناؤنس
کیا ایلکشن کمیشن نے ایناؤنس کیا
کہ کشمیر کے لئے ۲۱ مارچ اور جموں
کے لئے ۱۹ فروری ہوگی پنجاب
کے ساتھ ساتھ۔ فوری طور پر بدل گئے
ہم نے ریپریزنٹیشن کیا اور بچائے
مارچ کے اپریل کر دیا اور جموں کشمیر
میں ایک ساتھ کر دیا۔ ایلکشن کمیشن

نے فیصلہ کیا دیا۔ نہیں کشمیر میں
بھی ۲۱ فروری کو ہی چناو ہوگا
جبکہ کشمیر میں ۳۔ ۴۔ ۵ اور
۶۔ ۶ فٹ برف جمی ہوئی تھی۔ پہلی
تو یہ بات ہے پھر اس کے بعد ۲۱
جنوری آئی نامینیشن پیپرس داخل
کرتے تھے اور سب نے نامینیشن پیپرس
داخل کر دئے۔ ہم نے بھی اور دوسری
اور اپوزیشن پارٹیز نے اپنے نامینیشن
پیپرس داخل کئے اور میں بتلانا چاہتا
ہوں کہ ہم لوگوں کے ۱۴۱ نامینیشن
پیپرس فلمزیشنٹ گراؤنڈس پر ریجکٹ
ہوئے اور جسے کہ خود ایلکشن کمیشن
مانتا ہے۔

Not a single nomination paper of
the ruling party was rejected.

رٹل پوزیشن یہ ہے۔

Then we again approached the
President, the hon. Prime Minister,
the Home Minister and other Central
Ministers, put all these facts before
them.

اس پر ہم نے مطالبہ کیا کہ ان
ہول سیل ریجکشن کی وجہ سے اور
موسم کی خرابی کی وجہ سے ایلکشن
کو اینل کر دیا جائے یا پھر پوسٹپون
ہی کر دیا جائے لیکن نہ تو اسے اینل
کیا گیا اور نہ ہی پوسٹپون کیا گیا۔
میں نے چوہان کو خط لکھا کہ صاحب
کم از کم یہ توقع نہیں ہو سکتی
ایک ایسی گورنمنٹ سے اور ایک ایسی
سرکار سے جس نے ہندوستان کی ڈیموکری
کے لئے اپنا ہر ایک حق نیوچھا اور کیا
ہو۔ ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔

[شری بخشی غلام محمد]
 اور چوہان صاحب نے مجھے
 خط لکھا۔ میں وہ خط پڑھ کر سناتا
 ہوں۔

"I have your letter No.
 dated 7th January. I am forwarding
 a copy of this letter to Sadiq Saheb,
 with a request that he should look
 into your complaints personally and
 satisfy himself that nothing wrong or
 improper is done. I am very keen
 that the elections in Jammu and
 Kashmir, as in the rest of the coun-
 try, should not only be fair, but
 should also appear to be so, and that
 nothing should be done that can be
 regarded as at all unfair and impro-
 per."

یہ ہے چوہان صاحب کا خط۔
 اب اس سے اور ایک ہمت ہوئی ہمیں
 کہ ایلکشن فیئر اور امپارشیل
 ہونگے۔ لیکن جناب ہوا کیا۔
 ریجیکشنس ہوئے۔ ۲۶ آدمی اسمبلی
 میں انکنٹیسٹیڈ آگئے سٹریٹ اوے
 لہذا ۲۶ کی سٹرینگتہ بن گئی۔ اور
 پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو
 معلوم ہے۔ دیز آر آل اوپن سکیرٹس۔

These are all open secrets.
 بیلٹ باکسیس آئے ٹوٹے اور
 لٹس کے بغیر، سیل کے بغیر، بیلٹ
 پیپر ایکاونٹ کئے بغیر۔ ہم نے
 اعتراض کیا۔

No body just did anything or cared.
 لیکن کہا کہ ٹھیک ہے کاؤنٹ
 کیا جاوے۔ ایلکشن کمیشن نے
 دو آدمی یہاں سے بھیجے کشمیر میں
 اسے دیکھنے کے لئے
 with no instructions.

وہ بالکل کھڑے رہے بھوت کی طرح۔
 وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ
 ہم کیا کریں گے۔ اور پریشکلر کانسٹی
 ٹیوٹسی میں کیا ہوا۔ ۵۵ ٹوٹل
 سٹرینگتہ ہے اس بوتھ کی لیکن اس
 بکسے میں سے ۱۱۸۵ بیلٹس نکلے۔
 یہ ہوا۔
 (وہودہاں)..... اس پر
 بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہم ڈاکٹر کرن
 سنگھ جو اس وقت وہاں کے گورنر تھے
 اس سے بھی ملے سب سے ملے واویلا
 کیا راشٹر پتی سے ملے لیکن آخر کو
 ہم کو حکم ہوا کہ قانون اجازت
 نہیں دیتا۔ ہم اینل تو نہیں کریں گے
 کیونکہ باہر دنیا میں کیا کہا
 جائیگا۔ ہم نے کہا کہ باہر دنیا
 تو ہماری ناک کٹ گئی۔ انڈیا
 کے مطالب یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں
 الیکشن فیئر اور امپارشیل ہوتے
 ہیں۔ چنانچہ ہمارے شو کمار سین
 سوڈان اور ایچیٹ میں الیکشنس
 کرانے کے لئے کئے اور یہاں یہ ہو
 رہا ہے۔ خود سندرم نے کہا ہے۔

"that the nomination papers of a
 large number of opposition candidates
 were rejected on flimsy grounds is
 serious."

اور پھر وہ کہتے ہیں۔

"The difference in law is not satis-
 factory, and I intend recommending
 to the State Government that the
 State election law should be brought
 in line with the general election law
 on this point as soon as possible."

یہ سندرم کہتے ہیں کہ معاملہ
 سیریس ہے۔ ہمیں ہدایت دی کہ

جاؤ الیکشن کرو۔ ہم نے
کہا کہ اچھا۔ جب اور
کچھ نہیں ہوتا ہے تو بھی ایک
ہی ریمپڈی ہے کہ الیکشن پیش

فیصلہ ہوتا ستمبر تک کشمیر اسمبلی
میں ان کو پتہ لگ گیا کہ ایک ان
سیٹ ہو گیا۔

Because of uncontested return re-
jection of nomination paper.

That is the law of the country.

اور ہم اس کے سامنے جھکے۔ تو
جناب وہ بھی ماجرا سن لیجئے کہ
۵ الیکشن پیشش میں کشمیر
کی۔ آندھر پردیش میں ۱۲ تھیں
اور ۱۲ ڈسپوز ہو گئیں۔ ہریانہ میں
۱۳ تھیں اور اس میں سے ۱۲ کا
فیصلہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ مہا راشٹر
میں ۲۱ تھیں ۲۰ کا فیصلہ ہو چکا۔
میسور میں ۲۱ تھیں ۱۳ کا فیصلہ
ہوا ہے۔ جب کہ جموں اور کشمیر
۵ الیکشن پیشش تھیں
اور خدا کے فضل سے ایک کا فیصلہ
ہوا ہے۔ ریل سٹوری پر آئیے۔
ٹریبونل بنتا ہے۔ سندرم نے کہا لا
بدل دو۔

۲۵ اور ہونگے۔ تو انہوں نے ایک
دن میں لا بدل دیا اور وہ لا بھی
ایک دن میں اسمبلی بیٹھی۔ اور
اسے بدل دیا۔ ۹ ستمبر کو بدلا اور
۱۰ ستمبر کو ایسنٹ لے لی گورنر سے
۱۱ کو لاگو کر دیا۔ اور الیکشن
ٹریبونل سرکار نے مقرر کیا تھا وہ
عدالت میں بیٹھا ہوا تھا الیکشن
پیشش سننے کے لئے چیراسی گیا اور
اس کو کہا کہ

You are no more an election tri-
bunal, please go.

وہ ۱۱ کو ہوا اور ۱۱ کو جب یہ
ہوا میں پہنچا دوڑتے دوڑتے پھر
چوہان صاحب کے پاس۔ آخر کہاں
جائیں۔ حاکم تو بھی ہیں۔ ہم تو
انہیں سے بتائیں گے کہ آگے تفتیش
ان کا نام ہے۔ میں پھر آیا میں نے
لمبا چوڑا لکھا اور ان کو بتا دیا
کہ یہ لا پاس ہوا اور کیا کیا ہوا
اس طرح ایک دن میں۔

Bring it on a part with the rest of
the country—as early as February 67.

اسمبلی ملی مارچ میں۔ اس میں
لا پاس نہیں ہوا۔ اور پھر ہوا۔
ٹریبونل مقرر کیا انڈر دی اولڈ لا۔
ٹریبونل نے کام شروع کیا کر دیا۔
ایک کا فیصلہ دیا۔ یعنی اس کا شڈیول
تینا وہ ۲۶ کے فیصلے دینے والا تھا
ان دی متھ آف ستمبر.....
(ویودھان)..... تو پھر کیا ہوا۔ ۲۶
جو ان کنٹریڈ رٹرنز تھے ان کا

الیکشن ٹریبونل ختم ہو گیا۔
میں نے کہا کہ ایڈ ہاک جلد سے
حلد مقرر کیجئے۔ انہوں نے کہا
کہ میں جلدی کروں گا۔ یہ بات ہوئی
شاید ۱۳ ستمبر کو۔

[شری بخشی غلام محمد]

اور آج ستمبر بھی گیا - اکتوبر بھی گیا - نومبر بھی گیا - آج آخری تاریخ ہے نومبر کی -

نو مہینے ہو گئے ہماری پیشین کے - ۷۷ الیکشن پیشین میں سے ایک کا فیصلہ ہوا ہے اور خدا نے چاہا اگر یہی سینیڈا رہی تو کم سے کم ۱۰ سال ان کو چاہئے یہ فیصلہ کرنے کے لئے حالانکہ قانون ہے کہ ودن سکس مٹھس ہونا چاہئے - سہا راشٹر میں ۲۱ میں ۲۰ کا فیصلہ ہو گیا - ہریانہ میں ۱۵-۱۲ کا فیصلہ ہو گیا - بانی الیکشن بھی ہو گئے - لیکن کشمیر جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ سیشنل سبجکٹ ہے ۳۷۰ ہے ۳۸۰ ہے - ۳۹۰ ہے مجھے معلوم نہیں اور کون کون سے سبجیکٹس لاگو ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ آج تک اس وقت تک کوئی ایڈ ہاک جج مقرر نہیں ہوا ہے - جب کہ ہائی کورٹ میں وہاں تین آدمی مشتمل ہیں -

They are fully occupied with their own work.

وہ نہیں کر سکتے انہوں نے صاف کہا -

لیکن میں راشٹر پتی راجیہ کے متعلق کہوں تو انہیں نا منظور ہوگی بات - میں ایک بات کہوں گا - جو میرا خیال ہے انہیں پسند آئیگی - میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ مائنارٹی گورنمنٹ جو ہے جو اس طرح بنی ہے اور جس کے خلاف اتنے پیشین ہیں اس کو ٹسمن

کیجئے - یہ بھی آپ نہیں مانیں گے - مجھے معلوم ہے نہیں مانیں گے آپ - کشمیر سبجکٹ ہے - تو پھر میں عرض کروں گا آپ سے کہ آج نو مہینے ہو گئے ہیں - اب دسمبر - جنوری فروری اور مارچ چار مہینے ہیں - معمولی سا سبجکٹ آپ سے عرض کرتا ہوں - ہارڈ سبجکٹ ہے - ان چار مہینوں میں ان سب پیشین کا فیصلہ کرنا دیجئے -

And let there be fresh elections in April 68.

یہ میرا سبجکٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ججز کو مقرر کریں جو ان کنونشنز کا جلد سے جلد فیصلہ کریں - میں ایکسٹریمیٹ نہیں ہوں ایکسٹریم میں نہیں جاؤنگا - یہ ایک سبجکٹ ہے سہرانی کر کے امیڈیٹ اسٹیس لیجئے - ۱۳۱ کیسز کو ڈیسائڈ کرائیے - خاص طور سے ۲۱ کیسز اسمبلی کے ہیں جن کو ججیز کو مقرر کر کے ڈیسائڈ کرائیے - اگر یہ کیسز مارچ کے آخر تک ڈیسائڈ ہو جائیں تو فریش الیکشنز اپریل میں ہو سکتے ہیں - فریش الیکشنز سے میرا مطلب بانی الیکشنز ہے -

دوسری بات - یہاں پر کشمیر کو دی جانے والی سہایتا کے متعلق کہا گیا ہے - کشمیر آپ کا ایک غریب ساتھی ہے - جہاں بمبئی اور کلکتہ جیسے آپ کے امیر ساتھی ہیں وہاں کشمیر جیسا ایک چھوٹا اور غریب

ساتھی بھی ہے۔ اسلئے سہایتا تو اس کو دینی ہی پڑیگی۔ میں آپکی اطلاع کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۴۷ سے مارچ ۱۹۶۳ تک ٹوٹل گرانٹس اور لونز جو کشمیر کو ملے۔ وہ تھے تقریباً ۷۲ کروڑ روپیہ۔ لیکن ۱۹۶۳ سے ۱۹۶۶ کے آخر تک جو نئی سرکار کو ملے وہ تھے ۷۰ کروڑ روپیہ۔ یعنی دو سال میں انکو ۷۰ کروڑ روپیہ دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا دیکھ بہال کیجئے۔ میں یہ جو فگرز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مس فائینس ڈپارٹمنٹ کے سٹیٹمنٹ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ میری اپنی فگرز نہیں ہیں۔ بلکہ فائینس ڈپارٹمنٹ سے جو فگرز میرے پاس آئیں ہیں ان میں سے بنا رہا ہوں۔ کشمیر پر تھوڑا رحم کھائیے۔

پاٹودیا جی نے ایک بڑی ہی کنسٹرکٹو ایپروچ کی بات کہی ہے۔ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھئیے لیکن ان کو کام دیجئیے۔ وہاں پر کام دھندوں کا ایکسپانشن ہونا چاہئیے۔ انٹسٹریٹ ڈویلپمنٹ ہونا چاہئیے۔ ایگریکلچر کو بڑھاوا دیجئیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے۔ جینرل ایڈمنسٹریشن پر ۱۹۶۲-۱۹۶۳ میں ۶۱ لاکھ خرچ ہوا لیکن آج چار سال بعد وہ بڑھ کر ۱ کروڑ ۱۰ لاکھ ہو گیا یہ ایکسپانشن وہاں پر ہوا ہے۔ پولیس پر ۱۹۶۳-۱۹۶۴ میں ایک کروڑ روپیہ

خرچ تھا۔ لیکن اب وہ بڑھ کر پونے تین کروڑ ہو گیا ہے۔ یہ ایکسپانشن ہوا ہے۔ یہ فگرس میں کشمیر بجٹ سے پیش کر رہا ہوں۔ انٹسٹریٹ کے بجٹ میں ہم اس وقت ۲ کروڑ ۴۹ لاکھ روپیہ یعنی تقریباً ڈھائی لاکھ روپیہ خرچ کرتے تھے لیکن اب اس پر ۴۹ لاکھ روپیہ خرچ ہوئے ہیں۔ یعنی ڈویلپمنٹ کی چیز تھی ان کو روک دیا گیا۔ مسٹر ڈانگے یہاں بیٹھے تھے۔ وہ لیبر کے معاملے میں وہاں گئے تھے۔ ہماری سلک فیکٹری میں جہاں چار ہزار آدمی کام کرتے تھے وہاں اب ۵۰۰ سے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ کوکوٹز ۶۰ ہزار من پیدا ہوتی تھی وہاں اب ۱۰-۱۲ ہزار من پیدا ہوتی ہے۔ ۷-۸ مہینے سے وہ لوگ بیکار ہیں۔ اسلئے جناب میں چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر توجہ دی جائے۔

دوسری بات میں ہوم گارڈس اور فیلڈ سروے آرگینیزیشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ابھی ایفدایس۔ اے کا تذکرہ ہوا جس پر ڈیڑھ کروڑ روپیہ سے زیادہ خرچ ہونا ہے۔ اگر آپ ان کو ڈسمس کرینگے۔

سہت دگوجے ناتھ (گورکھپور) :
وے ہندو ہیں یا مسلمان۔

شری بخش غلام محمد : ہندو مسلمان سب ہیں۔ اب اگر ان دس ہزار آدمیوں کو آپ ڈسمس کرینگے

[شری بھٹی غلام محمد]

تو شاید ایک نئی پرابلم ایمپلائمنٹ کی کھڑی ہو جائیگی۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اندر جو اینٹی سوشل اینٹی نیشنل ایلیمنٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو ویڈ آؤٹ کیا جائے اور جو باقی بچتے ہیں ان کو ایبزارب کر لیا جائے اور ان کو آپ تھیٹر کمانڈر کو ہیڈ اوور کر دیں۔ آپ ان کو کہہ دیجیئے کہ سینٹر اس میں گرانٹ دیتا ہے ۹۰ فی صدی تک اور بورڈر ڈیفنس کے لئے ان کو رکھا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو چائنا بورڈر اور پاکستان بورڈر پر لگا دیجئے۔ کیا ضروری ہے کہ ان کو شری نگر یا انت ناگ یا بارا مولا میں ہی لگایا جائے۔ وہاں ان کا کیا کام ہے۔ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ڈسمنس کرنا مشکل ہوگا۔ لہذا آپ اتنی کرپا کیجیئے [ان کو بھرتی کیا گیا ہے ان کو اس کام پر لگایا جائے اور سٹریٹ اوے ان سے وہ کام لیا جائے۔ ان کو لداخ بھیج دیجیئے۔ چوشول بھیج دیجیئے۔ کارگل بھیج دیجیئے۔ بارڈر پر لگا دیجیئے۔ یہاں پر فوڈ کے سلسلے میں تذکرہ ہوا۔ واقعی ایلامنگ پوزیشن تھی۔ جب سیلاب کے سال میں یعنی ۱۹۵۷ سے ۱۹۵۹ میں ۶۰ ہزار ٹن ۶۲ ہزار ٹن سے زیادہ غلہ نہیں گیا۔ ہر قسم کا غلہ رائس، میز، جوار، باجرہ، وہیٹ وغیرہ۔ لیکن ۱۹۶۵-۱۹۶۶ میں میرے ایک سوال کے

جواب میں جو کہ مجھے کل ہی ملا ہے بتایا گیا ہے۔ کہ تین سال میں ۵ لاکھ ۵۸ ہزار ٹن گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔

یہاں پر کسی دوست نے شاید ایسا کہا۔ کہ کشمیر کو سستا غلہ دیا جاتا ہے۔ میں اس ہاوس کی اطلاع کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو بھی اسی قیمت پر غلہ دیا جاتا ہے جس قیمت پر دوسروں کو ملتا ہے۔ ہاں، کشمیر گورنمنٹ اس میں اپنی طرف سے سبسڈی دیتی ہے۔ اس کو گورنمنٹ آف انڈیا سبسڈی ائز نہیں کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ۱۹۵۷-۱۹۵۸ تک کرتی تھی۔ لیکن اب کشمیر گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کشمیر گورنمنٹ پہلے ٹو دی ٹیون آف ۱۲۵۰۰۰-۱۷۵۰۰۰ اور ڈھائی لاکھ تک کرتی تھی لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آٹھ کروڑ روپیہ تک کیا جا رہا ہے۔ اسلئے میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صادق صاحب نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ میں ڈیموکریسی میں ییلو کرتا ہوں۔ یقیناً اگر میرے زمانے میں ایک بار بھی گولی چلی تو میں اسی وقت کرسی چھوڑ دوںگا۔ لیکن

یہ کرسی جناب اتنی پیاری ہے کہ کوئی اس کو نہیں چھوڑتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بار وہاں پر گولی چلی۔ اس سرکار سے ہم کو تین چیزیں ملی ہیں۔ ۱۹۶۵ میں انڈو-پاکستان کا کانفلکٹ ہوا۔ بہت بڑا تحفہ ملا۔ ہمارے چوہان صاحب اس وقت ۳ اگست کوشری نگر میں تھے۔ انہوں نے اس وقت کہا۔

“There is no fear of infiltration and we have sealed the borders.”

On the 8th of August, in this very hon. House Shri Nanda announced that 12,000 infiltrators have reached Srinagar and they have surrounded Srinagar.

میں اس کی ڈیلیز میں نہیں جاتا۔ لیکن سوال پالسی آف لبرلائزیشن کا ہے۔ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے میں ایک بار بھی گولی نہیں چلی۔ ۱۹۵۳ سے لیکر ۱۹۶۳ تک ایک بار بھی لوگوں پر گولی نہیں چلی۔ ایک بھی سٹرائک نہیں ہوئی۔ لیکن ۱۹۶۳ سے یہ سب ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب تم کرا رہے ہو۔ بخشی فویا کہہ دیجئے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ۱۹۶۵ میں پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا تحفہ ملا۔ ۱۹۶۶ میں جموں سٹوڈینٹس پر فائرنگ ہوا۔ وہاں پر دفعہ ۱۴۳ لاگو کیا گیا۔ دفعہ ۱۴۳ تو جناب کشمیر کے آننے کا۔ کتاب کا ایک شیچوٹ بن گیا ہے۔

It is perpetual 144 since 1965 upto this time.

اور میں آپ کی آکھی کے لئے یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے ایلیکشن کے دوران بھی دفعہ ۱۴۳ کو نہیں اٹھایا گیا۔ ہم لوگ اجازت لیکر جلسے کرتے تھے۔ اگر اجازت ملتی تھی تو جلسہ کرتے تھے۔ اگر اجازت نہیں ملتی تھی تو نہیں کر سکتے تھے۔

It has become perpetual.

کرفیو کے سلسلے میں بھی عرض کر دوں۔ یہاں بنگال کی حالت یہ ہے کہ اگر ۲۳ گھنٹے کا بھی کرفیو لگتا ہے تو اتنا شور ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پانچ دن تک تو کرفیو کے نیچے بالکل بند ہی رہا اور ابھی تک بھی ناٹ کرفیو چلتا ہے۔ یہ حالت آج وہاں کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کی ڈیفیکٹیز کو جانتا ہوں ایک دوست نے یہاں کہا کہ جموں کشمیر راج میں راشٹر پتی راج کا مطالبہ کرنے سے اگر ہم راشٹر پتی راج وہاں پر لاگو کرینگے تو پاکستان کے ہاتھ میں ہم ایک ہینڈل دینگے تو میرا کہنا ہے کہ ہینڈل تو جناب والا ہم نے اسی دن پاکستان کو دے دیا جس دن کی یہ ۱۴۱ نامینیشن فارس ریجکٹ کر دئے اور تب سے وہ برابر دیا جا رہا ہے۔ مجھے فکر ہے کہ ڈیمو کریسی کا کیا ہوگا۔ باقی اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لئے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوںگا۔

[شری بخشی غلام محمد]

بہر حال یہ ایک نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کچھ ماڈریٹ اور پریکٹکل سچیشنس دئے ہیں اور ان کو ایکسپٹ کرنے میں آپ کو کوئی ڈیفکٹی نہیں ہونی چاہئے یا پھر کہئے کہ وہ آپ کی اس فارسی کے شاعر جیسی حالت ہے جس نے یہ لکھا ہے۔

”عمرے وائید کہ یار آید بکاد،“

تم بھی رہو ہزار سال اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے ہزار سال۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اور نہ یہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس لئے میں آخر میں بھی یہی عرض کر کے ختم کرونگا کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے کشمیر کے مسلمان۔ کشمیر کے ہندو۔ جموں کے ہندو و سکھ اور لداخ کے بودھ سب ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہندوستانی ہیں۔ ہندوستانی رہے ہیں اور آگے بھی وہ ہندوستانی رہنے والے ہیں اور وہ اس سے دور نہیں جائیں گے۔

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया कि मैं इस कश्मीर के बारे में कुछ कहूँ। बख्शी साहब से मुझे कुछ इख्तलाफ हो सकता है लेकिन कई बातों पर वाकई मैं उन से सहमत हूँ जो उन्होंने यह कहा कि कश्मीरियों पर यह इलजाम लगाना कि वह पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं यह बिल्कुल गलत बात है। वह एक ऐसा

इलजाम है जो शायद तौहीन की हद तक पहुंच जाता है।

कश्मीर के हालात को समझने के लिए कश्मीर के इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालिये और उससे आपको मालूम होगा कि जो बातें आप कह रहे हैं और जो बातें चन्द एक दोस्तों ने कहीं उनकी कोई बुनियाद नहीं है। यह सब जानते हैं कि कश्मीर में जब तहरीके आजादी शुरू हुई तो उसके सिपाही जो थे उनमें शेख अब्दुल्ला थे, खुद बख्शी गुलाम मुहम्मद थे और गुलाम मुहम्मद सादिक थे। इन लोगों ने वहां पर मुस्लिम कान्फ्रेंस शुरू की। उस वक्त कश्मीर में हमारे यहां के मौजूदा मिनिस्टर कर्ण सिंह के वालिद मर-हूम महाराजा हरी सिंह वहां के महाराजा थे (ब्यवधान) मेरी बात सुनिये। उस वक्त 1938 में मुस्लिम कान्फ्रेंस को नेशनल कान्फ्रेंस में बदलने का फैसला किया गया (ब्यवधान) सुनिये साहब। कोई सियासी दबाव नहीं था जिसकी कि वजह से वह हुआ बल्कि वह इसलिए हुआ कि कश्मीर के लोग जो थे वह बुनियादी तौर पर एक ऐसी आइडियोलिजी के साथ मुत्तफिक थे जिस में कि वह सैकुलरज्म और डेमोक्रेसी को अपनाना चाहते थे। अगर कोई आदमी यह कहे कि मैंने उस वक्त कश्मीर में कोई अलहदा रोल प्ले किया है तो मैं उस को मानता तो जरूर हूँ लेकिन बुनियादी बात यह है कि कश्मीरियों की रगों और नसों में यह फिरका-परस्ती का जहर नहीं भरा था और आज भी अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि कश्मीरी मुसलमानों के नाम के साथ हिन्दू का आखिर में थोड़ा नाम जुड़ा होता है और उसी तरह से कश्मीरी हिन्दुओं के नाम के आखिर में थोड़ा मुसलमान का नाम जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं आप को बतलाऊँ एक वहां जगन्नाथ पीर चीफ इंजीनियर होते थे बख्शी साहब के जमाने में। ऐसे ही काजी प्रेम नाथ नाम है।

7.24 hrs.

[SHRI S. M. JOSHI in the Chair]

ऐसे ही मुसलमानों के वहां पर नाम हैं जैसे अब्दुस अजीज नेहरू, गुलाम हबीबुल्ला पंत (व्यवधान)

SHRI PILOO MODY : Is he naming poets ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : What is he aiming at ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : आप नाराज मत होइये। मेरा यह सब बतलाने से मतलब यह था कि शुरू से ही कश्मीर के जो रहने वाले लोग थे उन में एकता थी। हर एक नेता जो भी वहां पर आया उसने अपना रोल अदा किया जिसमें शेख अब्दुल्ला का रोल भी है, बख़्शी साहब जो यहां पर बैठे हैं उन का भी रोल रहा है। अभी यह कहा जाता है कि कश्मीर में शायद कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि वहां नोनमुस्लिम का रहना व जीना बिलकुल दुश्वार है और वहां पर मुसलमान खूनी व खूँखवार दरिन्दों की तरह नोनमुस्लिम को मारना चाहते हैं जितनी जल्दी इस खयाल को दिलों से हटाया जाय, जितनी जल्दी इस नक्शे को मिटाया जाय वह बेहतर होगा . . .

(व्यवधान) मेहरबानी कर के खामोशी के साथ मेरी बात को सुनते चलिये। मेरा मतलब यह कहने का था कि कश्मीर की जो फ़िज़ा बनी हुई है फिरकेबाराना यगानगत की उस पर किसी को शक नहीं करना चाहिये। अब यह तो हो सकता है कि वहां पर डेवलपमेंट प्लांस अमल में न आये हों, वहां पर कभी कभी कोई खामी आई हो तो उस के लिए हम यह मांग करें कि यह प्रेसीडेंट रूल वहां पर होना चाहिए मैं समझता हूँ कि यह जायज़ बात नहीं है। बख़्शी साहब को हजारों शिकायतें हो सकती हैं एलेक्शन के मुताबिक और अभी उन्होंने एक काफी लम्बी चौड़ी तकरीर वहां के एलेक्शंस के मुताबिक की लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एलेक्शंस पेटिंशंस इस वक्त अदालत में हों तो उन पर कोई रायज़नी करना अच्छा नहीं होगा। . . .

श्री गुलाम मुहम्मद बख़्शी : मैंने कोई राय नहीं दी। मैंने तो एक वाक्या बयान

किया। वह किसी अदालत में नहीं है। मुझे मान्ज़ूम नहीं है कि वह कहां है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : बख़्शी साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि वह कहां पर है। जहां तक कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है अगर उस हुकूमत के साथ जनता नहीं है, अवाम का साथ उसे हासिल नहीं है तो इसका फ़ैसला ऐवान में किया जा सकता है, असेम्बली में किया जा सकता है। सड़कों पर यह इश्यू नहीं ले जाया जाना चाहिए। असेम्बली यह कहने का अधिकार रखती है कि वह यह कहे पार्लियामेंट को और सरकार को कि वहां पर मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है

SHRI BAL RAJ MADHOK : The charge is that the Assembly is not representative. It is hen-pecked; it is nominated. (Interruption) How can you prove it unless you hold the elections, unless the petitions are settled?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जनसंघ के कुछ सदस्यों ने काफी शिकायतें कीं कि कश्मीर में यह हो रहा है और कश्मीर में वह ज्यादाती हो रही है तो मैं उन की इत्तिला के लिए आर्गोनाइजर अखबार का सन् 63 का एक आर्टिकल पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त मेहरबानी करके सुनें : बख़्शी साहब ने कहा कि सन् 1953 से लेकर 63 तक एक बार भी 144 दफा वहां पर नहीं लगी तो आर्गोनाइजर इस बारे में क्या लिखता है वह जरा सुनें :

"The occasion was the mammoth public meeting organised by Shri Shafi Qureshi, a leading advocate of Kashmir Bar. . . . (Interruptions) on the minds of thousands of people gathered was Pandit Nehru's decision, in accordance with the Kamraj Plan, that Bakshi Gulam Mohammed should quit his office. Shri Shafi Qureshi's outspoken broad sides have evidently been giving sleep-

[श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी]

less nights to Bakshi Gulam Mohammad and Co.... (Interruptions) Please listen.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That is why you are the Deputy Minister here.

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : मेहरवानी कर के सुनिये :

"Within days of the above described meeting, Shri Shafi Qureshi has been served with a gag order, he has been prohibited for an indefinite period from making any public statement or addressing a public meeting in the State."

I went to the High Court against this order.

This is from the *Hindustan Times*

...

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Shall we listen to these personal disputes ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य खामोश रह कर सुनें। उन का वक्त खत्म होने पर मैं कुरेशी साहब को रोक दूंगा।

श्री य० द० शर्मा : विषय काश्मीर का है, विषय कुरेशी साहब का नहीं है।

श्री गुलाम मुहम्मद बखशी : मैं उन से कहता हूँ कि वह जहमत गवारा न करें, वह जो कुछ कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसका इलाज क्या है ?

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : आज जो लोग मांग करते हैं कि वहां पर संसद का राज्य होना चाहिये, जैसा कि एक दोस्त ने कहा वह हिन्दुस्तान या काश्मीर के हाथ मजबूत नहीं करते, वह यकीनन दुश्मनों के हाथ को मजबूत करते हैं।

श्री कंबरलाल गुप्त : माननीय मंत्री जी कैसे करना चाहते हैं, वह बतलायें न।

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : मैं बतलाऊंगा, अगर आप को सब्र हो। यह जो नफरत फैलाने का तरीका है, हिन्दू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा करने का जो तरीका है उससे आप हिन्दुस्तान की खिदमत नहीं करते, हिन्दुस्तान के वकार को ठेस पहुंचाते हैं।

काश्मीर में एक वाक्या हुआ, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया। एक परमेश्वरी देवी ने शादी कर ली मुसलमान लड़के के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर मुसलमान लड़कियों ने भी हिन्दू लड़कों के साथ शादियां की हैं। मगर कभी कोई शोर नहीं मचा।

श्री गुलाम मुहम्मद बखशी : जहां तक परमेश्वरी देवी का ताल्लुक है, मामला आपने उठाया और यह भी कहा कि मामला सब-जुडिस है इस लिये मैं उसके मेरिट्स में नहीं जाना चाहता

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : मैं केस की मेरिट्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि इस किस्म की चीजें वहां होती रही हैं और यहां भी होती हैं। एक ही कम्प्यूनिटी में ऐब्डक्शन के केस हो जाते हैं

श्री रामावतार शर्मा : (ग्वालियर) : सभापति महोदय, यहां पर जो चर्चा इस समय हम लोग कर रहे हैं वह इस लिये कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री की चर्चा का उत्तर आये। लेकिन अब हम यह देख रहे हैं कि वहां पर बखशी साहब और कुरेशी साहब का मुकाबला किया जा रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें, यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामावतार शर्मा : इन दोनों का आपस में मुकाबला किया जा रहा है, यह अपनी कह रहे हैं और वह अपनी कह रहे हैं। इससे क्या फायदा ?

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें एक मजहबी रंगत दी गई। यह बिलकुल

गलत तरीका है। फिर इस के साथ-साथ वहां पर ओवरनाइट एक ऐक्शन कमेटी आर्गेनाइज की जाती है। इस ऐक्शन कमेटी के पीछे कौन है, यह सब जानते हैं। वही लोग जो सब से पहले हमला करना चाहते हैं, हल्ला करना चाहते हैं, उन मर्कजों पर जहां अभी तक कम्यूनलिज्म फला फूला नहीं है। उन का मकसद यह है कि तमाम उन हिस्सों में जहां शांति और अमन है, जहां के लोग भाई-चारा कायम रखते हैं, वहां मजहब के नाम पर फूट डाली जाये और मजहब के नाम पर इन्सानों को तकसीम किया जाये, और इस के लिये काश्मीर को अट्टा बनाया जाये।

17.30 HRS.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

लेकिन कश्मीरियों को एक बार फिर मौका मिला। एक दफा उन्होंने 1947 में अपना मेटल जाहिर किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ऐग्रेसन किया तब उन्होंने अपना मेटल जाहिर किया। इस वक्त जो लोग उन पर शक करते हैं वह वही लोग हैं जो जम्मू छोड़ कर पठानकोट चले गये थे। यह ऐसे गैरतमन्द लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक सीरियस मैटर है। आज हम को श्री बलराज मधोक का सटिफिकेट नान-कम्यूनलिज्म के नहीं चाहिये। हम जो कुछ भी हों, हिन्दुस्तान के हैं, हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान के रहेंगे और हिन्दुस्तान में मरेंगे अगर कोई यह समझता है, कोई जमात यह समझती है...

श्री बलराज मधोक : सटिफिकेट हमारा नहीं, अपने दिल का लो। (व्यवधान)

श्री कंबरलाल गुप्त : मैं और कुछ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन यह बतलाइये कि वहां पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं या नहीं? अगर लगाये जाते हैं तो आप उसको कैसे रोकेंगे? यहां पर आयूब साहब जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं। आप को इस पर शर्म नहीं आती और आप इसको डिफैन्ड करते हैं। आप के आदमी इस तरह के नारे लगाते हैं। आप बेकार की बातें

L88LSS/67-11

करते हैं। आप को पता नहीं है। हिन्दुस्तान के इलाके में क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे? नहीं लगेंगे। अय्यूब जिन्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. The House listened to all the speeches so far with rapt attention and it was good. We are discussing the situation in a particular area which is very vital. If the hon. Member goes on interrupting Mr. Qureshi, it would be very difficult. Whatever he wants to say, he can say. The Home Minister will reply at the end and the hon. Member can put questions at that time. So far as this argument is concerned, he may please not interrupt Mr. Qureshi. He has to conclude.

श्री कंबरलाल गुप्त : मेरे सवालों का जवाब दिया जाये (व्यवधान)

श्री मुहम्मद शक्की कुरेशी : मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी मुल्क के हिस्से में कोई आदमी वतन से या कौम से गद्दारी करता है, ब्याह वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वह गद्दार है। किसी एक मजहब में नहीं, गद्दार हर मजहब में पैदा होते हैं, हर सूबे में पैदा होते हैं, हर कौम में पैदा होते हैं। किसी भी खास कौम के बारे में यह कहना उस कौम के साथ दुश्मनी करना है, अदावत करना है।

मैंने साबित कर दिया है, और मुझे याद है, बख्शी साहब को भी भूलना नहीं चाहिये कि जिन लोगों ने देश के लिये अपनी जानें दी हैं, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया है, उन पर भी इल्जाम लगाये जाते हैं कि वह पाकिस्तान के एजेंट हैं। इस किस्म की बात का विरोध किया जाना चाहिये। मैं साबित कर के दिखाऊंगा कि जो पहले बख्शी साहब और शेख साहब की तारीफें करते थे, वही आज कहते हैं कि यह लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म और जुर्म नहीं हो सकता। हम हज़ार इत्त-साफ रखते हों...

श्री गुलाम मोहम्मद बखशी : यहां पर कम्पलिकेशन पैदा हो रहा है काश्मीर के सिल-सिले में। मेरे खयाल में न इस तरफ के मेम्बरों को काश्मीरी मुसलमानों से कोई शिकायत है न उस तरफ के मेम्बरों को। किसी ने ऐसी बात नहीं कही। जो काश्मीरी हिन्दू हैं वह रिनेगेड हो सकते हैं, काश्मीरी मुसलमान गद्दार हो सकते हैं, लेकिन यह शिकायत किसी ने नहीं की है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बखशी साहब ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री की तकरीर नहीं सुनी।

श्री कंबरलास गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : On what point of order?

श्री कंबरलास गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं वह एक गलत इम्प्रेसन पैदा कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा है काश्मीरी मुसलमानों को कि वह गद्दार हैं। यहां पर किसी के कहने का मंशा नहीं है कि काश्मीरी मुसलमान गद्दार हैं। इस तरह के कहने का मतलब होगा कि यह गलत इम्प्रेसन पैदा हो जाएगा और सारे संसार में यह बात जायेगी। किसी ने भी नहीं कहा है कि मुसलमान गद्दार हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That was cleared by Mr. Bakshi just now. There is no point of order and if that impression is created, he has already disabused the mind of the House. Please continue.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने यह बात इसलिये कही कि मेरे मोअजिब दोस्त श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि वहां हिन्दू महिलाओं का सिन्दूर लूटा जा रहा है, वहां उनकी अस्मत् लूटी जा रही है लेकिन मैं हाउस से कहना चाहता हूँ कि

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, फिर यहां गलतबयानी पर मुझे खड़ा

होना पड़ रहा है। यहां पर आप के आदमी हैं, जो एक एक शब्द नोट करते हैं, टेप रिकार्ड हैं, जिस पर एक एक शब्द अंकित होता है। मैंने कहा था कि अगर आप ने काश्मीर को इतने अरबों रुपये व्यय करने के बाद और हजारों बलिदान देने के बाद फिर अपने हाथों से छोड़ दिया तो इन हजारों बलिदानों और जिन महिलाओं के सुहाग के सिन्दूर लुटे हैं, उनकी कुर्बानी पर आप धूल डालेंगे। मैंने यह कहा है। यह इसको कहां ले जा रहे हैं। आप उन से कहें कि वह हिन्दी सीखें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं अर्ज कर रहा था कि आज यह आदत हो गई है

SHRI BAL RAJ MADHOK : We are not here to listen to a personal dialogue. Let him reply to the charges.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : आप खामोश रहें तब तो मैं कुछ कहूँ।

SHRI A. K. SEN (Calcutta, North West) : On a point of order, I must support Bakshi Saheb and others. Nobody, whether on the Opposition side or on our side has cast any aspersion on the Kashmir Muslims. They are our brothers; they are part and parcel of this country and it will be a wrong thing to answer a charge like that. It will create confusion in the public mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In order to avoid further controversy I would like to point out to the hon. Member one thing. I have listened to all the speeches very carefully. The main problem is about the Kashmir administration. Communal aspect of it has nobody highlighted, so far as I understand. As far as possible avoid that also.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI (Kendrapara) : Is he intervening in the debate as a Member of the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is a Member of the House.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक और बातों का ताल्लुक है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन

नहीं चल रहा है, फंडज जो गए हैं उनका दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों को सुन कर मुझे हैरानी हुई है। मुअज्जिद मैम्बर बख्शी शाहब 1963 तक वहाँ चीफ मिनस्टर थे। उनके वक्त भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। लेकिन एक बात का मुझे दुख जरूर है। प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा है कि जो गल्ला काश्मीर में जाता है वह वहाँ से स्मगल हो कर पाकिस्तान को चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इस वक्त हमारी सरहदों पर हमारी सेनायें बैठी हुई हैं और वही हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं। अगर इस तरह की बात हम कहें कि गल्ला स्मगल होकर पाकिस्तान चला जाता है... (इंटरप्शन)

SHRI BAL RAJ MADHOK : How is it an aspersion on the Army ?

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : अगर उसके होते हुये गल्ला पाकिस्तान चला जाता है....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his arguments very carefully and also the other arguments. Let him not bring in the Army and other such matters.

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर यह इलजाम है कि गल्ला वहाँ से पाकिस्तान को भेजा जा सकता है, जैसा इल्जाम उन्होंने लगाया है तो मैं इस में कौन सी गलत बात कहता हूँ कि जब मैं यह कहता हूँ कि साहब ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि एक एक इंच सरहद की हिफाजत हमारी फौज करती है और हमें इस बात का फर्क है एक मक्खी भी इस तरफ से उघर नहीं जा सकती है और जो हिन्दुस्तान का माल है वह उघर नहीं जा सकता है। इस वास्ते यह जो इलजाम है यह बेबुनियाद है।

SHRI J. B. KRIPALANI : Our Army was there when thousands of infiltrators went into Kashmir. What is the hon. Minister talking about ? He is talking through his hat.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already ruled and pointed out to the hon. Member not to refer to those aspects.

श्री य० इ० शर्मा : सरहदों से मक्खियाँ नहीं आया करतीं, दुश्मन आया करते हैं।

श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी : एक बात का मुझे निहायत दुख है। हमारे बुजुर्ग मैम्बर बैठे हुये हैं जो शायद मेरी बातको सुनना पसन्द नहीं करते हैं। मैं उनसे नहीं कहता हूँ कि वह मुझ से इत्तिफाक करें। उन्हें मुझ से इकतलाफ राय रखने का पूरा हक है। लेकिन मुझे भी एक मैम्बर की हैसियत से अपनी बात कहने का हक हासिल है। मैं तबक्के करता हूँ कि वे मेरी बात को सुनेंगे। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन झूठी नहीं हो सकती है।

सादिक साहब ने लिबरलाइजेशन की जो पालिसी वहाँ शुरू की है उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि काश्मीर को आप डंडे के जोर से, कोई लालच दे कर या उस पर दबाव डाल कर अपने साथ नहीं रख सकते हैं। काश्मीरियों के दिल ने इस बात को चाहा था कि वे हिन्दुस्तान में आयें। हमें उसी रवायत को बरकरार रखना है। अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर से वहाँ पर अमन कायम रह सकता है, तो अमन कायम रह तो सकता है लेकिन वह अमन कब्रिस्तान का अमन ही हो सकता है, असली मानों में अमन नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि काश्मीर के लोग सही मानों में और सही तरीके से महसूस करें कि वे लोग हमारा जुब हैं तो फिर हमें चाहिये कि हम उनके लिए कारोबार के दरवाजे, नौकरियों के दरवाजे, आने जाने के दरवाजे खुले कर दें, उनमें एतमाद पैदा करें कि जो फंसला उन्होंने 1947 में किया था वह फंसला सही फंसला था। उनमें यकीन पैदा होना चाहिये.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is voicing his grievances against the Central Government. This will create a wrong impression in the world.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is concluding. Let him not be interrupted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं बिल्कुल गलत इम्प्रेशन नहीं दे रहा हूँ।

SHRI BAL RAJ MADHOK : I would like to make this very clear. Kashmir is part of India, not because of him or anybody else. Kashmir is part of India because of accession; Kashmir is part of India because our Army had gone and cleared most of the areas occupied by the Pakistanis; Kashmir is part of India because it has been so historically and geographically for thousands of years; Kashmir is part of India not because of him or anybody else. So, this kind of impression which the hon. Member is trying to create should not be allowed to go out.

AN HON. MEMBER It is part of India because of the people of Kashmir also.

SHRI SHAFI QURESHI : It is part of India because of the people of Kashmir also. I must say that also.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Not at all. Kashmir is part of India. If anybody does not want to live in Kashmir, he can go to Pakistan or anywhere else. Kashmir is part of India. Let it be clear to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a wrong impression that he is creating that Kashmir is part of India because of accession. It is part of India because the people of Kashmir opted for India. That is the main thing. So, let him not over-emphasise the other things.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : I do not think that the Chair should enter into arguments with Members.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : The Kashmiris fought the Pakistani Army and infiltrators in 1947 without the help of the Indian Army. The Army came in at the last stage when they had reached up to Srinagar. It was the National Conference that

fought them and the people of Kashmir that fought them. The people of Kashmir constitute Kashmir; Kashmir with its people is part of India; Kashmir without its people means mountains and snow only.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं एक बात कम्युनल एलीमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूँ। बलराज मधोक जी ने जो अभी लफ्ज का इस्तेमाल किया है यही वह लफ्ज था जिसने काश्मीर में आग लगाई। उन्होंने कहा कि जो काश्मीर के लोग हैं वे पाकिस्तान चले.....

SHRI BAL RAJ MADHOK : I have said that anyone who says that Kashmir is not India, can go away from India. Nobody can stop him. Shri Nehru has said this, Shri Chavan has said this, everybody has said this. I have said nothing new. Nobody who is in India and who does not want to live in India can be forced to live in India.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूँ। गलत या सही माननीय सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। ज्यादा तर गलत ही कह रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि काश्मीर को बलराज मधोक के सटिफिकेट की जरूरत नहीं है। बलराज मधोक जी ने कहा था कि भेरे सटिफिकेट की जरूरत नहीं है तो अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें। मैं चाहता हूँ कि यह हटा दिया जाए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his argument. I have made some observations after that. There is no point of order.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बकशी साहब की नाराजगी को मैं समझता हूँ। जनसंघ की नाराजगी को भी मैं समझता हूँ। यह वह जमायत है जिसने जम्मू में बड़ी बुरी तरह मार खाई है। जम्मू के मुतालिक किसी ने भी नहीं कहा है कि वहाँ इलैक्शन रिट्स थे। जनसंघ के पंडित डोगरा या बलराज मधोक जी या शास्त्री जी ने जो कुछ कहा है वह बेसो

के बारे में ही कहा है। जम्मु जनसंघ बांच के जो सेक्रेटरी थे श्री श्रद्धि कुमार कौशल वह वहां पर हार गए.....

श्री कंबरलाल गुप्त : कांग्रेस के जो प्रेजीडेंट हैं वह भी तो हार गए हैं।

श्री महम्मद शफी कुरेशी : दुख इस बात का है कि यह जमायत जो कि इतने किलेबन्दी कर रही थी और छ्वाब देख रही थी कि इसके आठ या नौ मेम्बर जीत जायेंगे, इसकी पहले जितनी स्ट्रेंथ थी, उतनी स्ट्रेंथ में भी यह नहीं आ सकी। बरूणी साहब की नाराजगी का मुझे एहसास है और हाउस को भी मैं समझता हूँ होगा। वह बहुत बिटर हैं हम से इस बात पर कि वह समझते हैं कि वहां पर इलैकशंज रिट्स हुए। कैसे इलैकशन हुआ मैं इस बात में अब जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कहा गया है कि फलां जगह पर सड़क नहीं बनी, पुल नहीं बना इस वास्ते वहां पर प्रेजीडेंट का राज नाफज किया जाए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनोखी दलील है। अगर इस बिना पर कि किसी जगह पर तरकियाती काम नहीं हुआ है, स्कूल नहीं खुला है वहां पर प्रेजीडेंट का राज्य कायम कर दें तो हमें हर सूबे में प्रेजीडेंट का राज कायम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों से हमारे इन दोस्तों को रंगीन चश्मा उतार देना चाहिए। इनको चाहिये कि काश्मीर को यह समझें, काश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कनों को समझें। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्होंने इस बहस को यहां न उठाया होता।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान के बक्कार के लिए, हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए हमें अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : सदन के सामने जो सवाल है इसमें कोई शुबहा नहीं है

कि यह एक महत्व का है और इसका हल हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। यहां बताया गया है कि बंगाल में यह हुआ, राजस्थान में यह हुआ। दूसरी जगह और कुछ हुआ होगा। लेकिन काश्मीर की जो हालत है उसकी मैं हमारे दूसरे जो राज्य हैं उनसे मुकाबला नहीं करना चाहता। हमारे देश की हालत तो खराब है ही और अगर काश्मीर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है तो हमारे देश की आजादी के लिये वह खतरा बन सकती है। इसलिए इस चीज को हम लोगों को गम्भीरता से सोचना चाहिये। संस्कृत में कहा जाता है—

गंडस्य ऊपरी पीटिका संवृत्ता

एक बायल पहले से था और उसके ऊपर एक और हुआ। देश की हालत वैसे ही खराब है। इस बात को हम रोज-रोज कहते रहते हैं। लेकिन काश्मीर की जो बात है उसको हमें ज्यादा गम्भीरता से लेना होगा और उस पर सोच विचार करना होगा।

मैं यह समझता हूँ कि इस बारे में कोई एक्स्ट्रीम स्टैप लेने से हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

यहां कहा गया कि हमलोग सेकुलर है। मैं मानता हूँ। मैं भी सेकुलर हूँ। लेकिन इस बात का दावा हमें नहीं करना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में, अपने आचरण में, सेकुलरिज्म को अच्छी तरह से ला रहे हैं। यह नहीं होता है। यहां पर कुछ भी कहा जाये, लेकिन जो कोई भी सवाल खड़ा होता है, कोई कहता है कि वह साम्प्रदायिकता का सवाल है, कोई कहता है कि वह प्रांतीयता का सवाल है, और कोई कहता है कि वह जातीयता का सवाल है, लेकिन आखिर में वह पोलोटिकल सवाल हो जाता है।

काश्मीर का जो सवाल हमारे सामने है, वह एक पेचोदा सवाल है। यहां सब लोगों ने कहा कि काश्मीर के मुसलमान और हिन्दु भारत में रहना चाहते हैं। मुझे भी इस में कोई शुबहा नहीं है। मगर अगर वे भारत

[श्री एस० एम० जोशी]

में रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को वहां ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए, जिस के कारण हमारे विरोधियों और शत्रुओं को हमारे विरुद्ध लाभ उठाने का मौका मिले। मैं जानता हूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ गलत काम हो रहे हैं। जैसा कि श्री बख्शी ने बताया है, रुपया पैसा और अनाज बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है ?

मैं समझता हूँ कि अगर हम ने काश्मीर के मामले को हल करना है, तो हम को उस का पोलिटिकल सालूशन निकालना होगा। यह तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि आज वहां का जो हुकूमत है, उस के पीछे वहां की जनता नहीं है। अगर आज कोई कहे कि ऐसा नहीं है, तो मैं इस को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर हम अपने यहां, अपने देश में, जम्हूरियत और लोकतंत्र चाहते हैं, तो हमें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि वहां की जनता जिस हुकूमत पर विश्वास करे, ऐसी हुकूमत वहां पर बनाई जाये। अगर हम यह काम नहीं करेंगे और कानून की बाल की खाल निकाल कर कहते रहेंगे कि वहां पर इलेक्शन हुआ है, वहां की हुकूमत के बारे में फ़ैसला वहां की एम्बेस्ली को करना होगा, तो इस तरह यह समस्या हल होने वाली नहीं है। बंगाल के बारे में यह बात कही गई, वह ठीक है। राजस्थान के बारे में भी यह बात कही गई और हम ने सुन लो। लेकिन अगर काश्मीर के बारे में भी सरकार यही बात कहेगी, तो मैं समझता हूँ कि मामला और भी पेचीदा होना चला जायेगा।

मैं यह मानता हूँ कि यह सबाल सिर्फ़ अपने तक ही महद्द नहीं है। स्वर्गीय शास्त्री जी ताशकंद में गए और एक श्रद्धा के साथ उन्होंने यह एग््रीमेंट किया कि हम दोनों पाकिस्तान और भारत, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे, जिस से हम भाई-भाई बन कर रहेंगे। उन्होंने श्रद्धा से यह एग््रीमेंट किया। मैं भी वही

श्रद्धा वाला आदमी हूँ। लेकिन सिर्फ़ कहने से नहीं होगा। उस के लिए हमें माहौल बनाना होगा। शास्त्री जी के चले जाने के बाद हमारे देश में जो माहौल, वातावरण, बन रहा है, वह ताशकंद की स्पिरिट को आगे नहीं बढ़ा रहा है। काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उस से ताशकंद की स्पिरिट आगे नहीं बढ़ेगी। वहां पर राष्ट्रपति की हुकूमत लागू करने से यह मामला तय होने वाला नहीं है। हमें इस समस्या का एक पोलिटिकल सालूशन निकालना होगा, वहां की जनता को अपने साथ लेना होगा।

श्री बख्शी ने इस बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। वहां के मुख्य मंत्री, श्री बख्शी और अगर जरूरत हो, तो शैब अब्दुल्ला भी, मंत्री महोदय को इन सब लोगों के साथ बैठ कर कोई सालूशन निकालना होगा। अगर वह कोई सालूशन निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह ताशकंद की स्पिरिट को आगे बढ़ा सकते हैं।

मेरा विश्वास है कि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ है, वह बिल्कुल अनैसर्गिक है, आर्टिफ़िशल है। वह बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। अगर हम लोगों को वह बंटवारा खत्म करना है, तो वह हम गौली से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे का जो हमारा मकसद है, उस को पूरा करने के लिए हम को एक नीति अख्यार करनी चाहिए। श्री बख्शी का जो सुझाव है, उस का मैं समर्थन करता हूँ। मैं गृह मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी तजवीब निकालें, जिस से वहां की हुकूमत को जनता का ज्यादा बहुमत मिले। अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो यह मामला तय हो सकता है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (वेगुसराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर की जो समस्या है, वह काफ़ी पुरानी, काफ़ी महत्वपूर्ण और एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें अफ़सोस है कि जब हम इस राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने लगते हैं, तो दलगत, व्यक्तिगत और साम्प्रदायिक भावभावों उभर आती हैं। यदि ऐसा न होता, तो अभी इस संदन में श्री बख्शी

और श्री कुरेशी का जो ब्राह्मण हम ने देखा, शायद वह न देखना पड़ता और न ही हमारे जनसंघ के भाई कम्युनिष्ट नेताओं के वहां जाने पर आपत्ति प्रकट करते। इस लिए इस सदन से पहले मुझे वह दरखास्त करनी है कि हम सब काश्मीर की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या, तमाम दलों की समस्या के रूप में देखें, किसी एक दल की समस्या के रूप में नहीं।

काश्मीर अस्त-का है, काश्मीर भारत का रहेगा और यदि किसी दूसरे देश ने इस पर महला किया, तो हम भारत के प्रकाश करोड़ों आदमी उस का मुकाबला करेंगे। यदि किसी दूसरे देश के लोग वहां पर घुसपैठ करते हैं, तो हम उस का मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ और मेरी पार्टी समझती है कि हमारे लिए काश्मीर की जनता के दिल को, मन को और क्विबल को जीतना बहुत ही आवश्यक है। पिछले बीस वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरह के शासन वहां पर सत्ते हैं, उस से वहां की जनता का एक भारी बहुमत हम से अलग हो गया है, उस का दिल दुख गया है, उस का मन भर गया है। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए उस जनता के दिल और मन को जीतें।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि काश्मीर को ज्यादा पैसा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि काश्मीर के लिए हमारी माताओं ने अपनी गोदें खाली की हैं, हमारी बहनों ने अपने सुहाग लुटाए हैं। अगर हमें काश्मीर की जनता को खिलाते-पिलाते के लिए और इस की उन्नति के लिए कुछ करोड़ खर्चा देना पड़ेगा तर्क काश्मीर हमारे साथ रहे, तो वह हम करेंगे और वह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए।

इस बात पर भी आपत्ति की गई कि कम्युनिष्ट नेता काश्मीर आये हैं। क्यों? क्या कम्युनिष्टों के लिए काश्मीर जाना अवैध है? वहां पर दफा 144 तो नहीं लगी है। जब अधीक साहब का राज होगा और वह दफा 144 खो देंगे, तो हम देखेंगे—हम उस का

मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के महामंत्री को काश्मीर जाने की आवश्यकता हुई तब, जब कि 22 अगस्त को जनसंघ के अध्यक्ष ने वहां पर एक ऐस साम्प्रदायिक उत्तेजना का भाषण दिया,

श्री बलराज मधोक : मैंने गृह मंत्री को कहा कि वह मेरे भाषण को पढ़ें। क्या माननीय सदस्य ने उस को पढ़ा है ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : ... जिस से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान-पक्षियों को काश्मीर में साम्प्रदायिक भावनायें उभार कर काश्मीर को और भारत को कलंकित करने का मौका मिला। मैं जनसंघ के भाइयों से दरखास्त करूंगा कि यदि उन को देश प्यारा है, यदि वे काश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वे ऐसी बात न कहें, ऐसा काम न करें, साम्प्रदायिकता की ऐसी भावना न पैदा करें, जिस से पाकिस्तान के भीतर के मुस्लिम सम्प्रदायवाद को उभारने का मौका मिले। मुस्लिम सम्प्रदायवाद और हिन्दू सम्प्रदायवाद दोनों देश के दुश्मन हैं, काश्मीर के दुश्मन हैं, काश्मीर को भारत में रखने के दुश्मन हैं। काश्मीर और भारत की रक्षा के लिए हमें इन दोनों सम्प्रदायवादों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।

काश्मीर पर राष्ट्रपति शासन लाद कर इस समस्या का हल नहीं होगा। वहां पर राष्ट्रपति शासन लादना पाकिस्तान को मदद करना होगा। लेकिन वहां पर शासन में जो प्रजापक्ष है, वहां पर नागरिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उस का निराकरण करना चाहिए, ताकि वहां पर जनतंत्र विकसित हो सके।

श्री महन्त विविजय नाथ : क्या केवल कम्युनिष्ट ही इस देश के रक्षक हैं, हिन्दु और मुसलमान नहीं ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम तो सब को मानते हैं। हम तो माननीय सदस्य को भी मानते हैं अगर माननीय सदस्य को शक हो, तो दूसरी बात है।

18 Hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Ramamurti.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thought...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have already taken two hours and some minutes. We will have to conclude this debate today. May I know how long the House is willing to sit?

श्री महन्त विभिन्नजय नाथ (गोरखपुर) :
हमें भी तो अधिकार है बोलने के लिए। हमें कब समय मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप को भी मिलेगा।
जरा आप सन्न करिए।

श्री राम गोपाल शालबाले (चांदनी चौक) :
मेरा भी नाम है। और लोगों को समय देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं ? मुझे समय मिलेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

I cannot allow any more.

SHRI P. RAMAMURTI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the scope of the debate on this motion has been widened and the whole gamut of questions including the present position of Kashmir, what should be done and all sorts of things have been referred to here. It has been a very good debate in this sense that Shri Bakshi Gulam Mohamud gave us a very vivid picture of how the elections were conducted and how the election petitions are being disposed of. He also told us what progress the various tribunals have made and how laws are made over-night in order to thwart the judgments of tribunals. All these things have been said here.

Therefore, the picture that emerges is that the present government there is not a democratically elected government. Very good. But in 1964 when there was that Hazarat Bal incident and a lot of trouble was there, at that time also it was stated on the floor of this

House that all that trouble was not only because of Hazarat Bal trouble or the 'holy hair' incident, but because of the fact that the people of Srinagar or the people of Kashmir were extremely angry against the then Government, the Government of Shamsuddin Sahib.

The fact is, therefore, very clear—I do not want to go into the history—that section 144 has been there in Srinagar continuously for 14 years. I know even on the day of Prophet's birth day they were not allowed to take a procession because prohibitory order under section 144 was there. This sort of thing has been continuing there.

Is it not necessary for us to understand why is it that the ordinary democratic rights of the people of Kashmir are not accepted? There must be some reason behind it. Why is it so? Why is this Government afraid of the democratic rights of the people of Kashmir? Why do you want to rule them permanently by means of orders under section 144, by means of prohibitory orders?

What is the way out? A way out has been suggested that there must be President's Rule and there must be ever so many other things, section 370 of the Constitution must be made applicable to Kashmir and all that. I would very much appreciate these things if as a result of these things the problem of Kashmir would be solved. But the fact remains that the democratic rights of the people there have been suppressed all these years despite the fact that we have been giving them some Rs. 70 crores as subsidy up to 1964 and subsequently another Rs. 72 crores. Why? As I said, there must be some reason. After all, the Government must be afraid of their democratic rights. Whether it is the Government of Sadiq or Shamsuddin or the Government that existed before it is immaterial, but it is a fact that all these years their democratic rights have been suppressed.

That is the situation with which we are faced. Therefore, it is not a question of imposition of President's Rule. If President's Rule can get them back all those democratic rights—as if that

is going to get them back because we know President's Rule in so many other States—I can understand that. But President's Rule is not going to give the people their democratic rights. Therefore, the problem is more fundamental, much more deep. I agree with my hon. friend, Shri Joshi, who said that there is no use thinking there is no problem of Kashmir. There is a problem. If there is no problem of Kashmir, we will not be discussing this on the floor of the House year after year. Do not shut your eyes to the fact that there is a problem and that problem cannot be solved by simply saying the Constitution should be made fully applicable. That is not the issue here. This problem cannot also be solved by the way in which Shri Madhok wants it to be solved—if anybody is feeling that he is not secure here, let him go to Pakistan. That way also it is not going to be solved. Neither is it going to be solved by telling the Hindus there "be sure of the fact that 40 crores of Hindus of India are behind you." That is not the way in which the Hindu population of Kashmir can be protected. The Hindu population of Kashmir can be protected only if the Muslim population of Kashmir is appealed to once again of the grand traditions of the Muslims who have been non-communal even in the year 1947, even at the time of the dastardly attack from Pakistan, even at that time they had adopted that non-communal attitude, and placing before them the glorious traditions of their non-communalism and secularism. That is the only way in which the Hindu population of Kashmir can earn its security and not by saying that 40 crores of the people of India are behind them "we are there to save you" and all that kind of thing, because that is the way of fanning communalism and not solving the problem.

Therefore, the problem is somewhat more fundamental. How can this problem be solved? I agree with my hon. friend that the only way in which it can be solved is by having some kind of consultation, real consultation, with the leaders of Kashmir itself and, in

that leadership, naturally Shri Sheikh Abdulla has an important place. You cannot wish him away by simply shutting him in jail for years together. You cannot say that he has ceased to be the leader of Kashmir. By keeping him in detention you cannot take away the affections of the people of Kashmir for him. So long as he commands the affection of the people of Kashmir, the only way in which it can be solved is by bringing all these people together.

That is the only solution that is acceptable to the people of Kashmir. Win the confidence of the people of Kashmir by doing that and see to it that no outside power is able to take advantage of this particular situation. That is the only way in which I wish this Government to move and I urge upon the government to move on these lines very quickly.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़):

उपाध्यक्ष महोदय, काफी सदस्यों ने बहुत कुछ काश्मीर के बारे में कहा और यह सही बात है कि उसमें से बहुतों ने जो कुछ कहा है उसमें काफी सच्चाई है कि यह समस्या साम्प्रदायिक जितनी नहीं है उतनी आर्थिक है। जो काश्मीरी पंडितों को पिछले दिनों परेशानी हुई या जो उन्होंने आन्दोलन किया या जो वहां के मुसलमानों के बीच में हुआ उसकी बुनियाद में अगर हम जायं तो मैं तो समझती हूँ कि इसकी बुनियाद आर्थिक है। अगर हम देखें काश्मीर का इतिहास तो आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि 1931 में काश्मीरी जनता ने एक बहुत बड़ा आन्दोलन किया था जब वहां महाराजा का राज था। इसी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मांग थी। वह उस मसय बिल्कुल डोर और बकरी का जीवन बिताते थे। इतनी गुबंत वहां थी और उस गरीबी का अन्दाजा बहुत लोगों को हुआ है जो काश्मीर गए हैं। आप शायद यह भी जानते होंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि उन दिनों एक समिति बनाई गई थी, ग्लांसी कमीशन जिसका नाम था और उस ग्लांसी कमीशन ने खुद इस बात का

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

एकरार किया था कि वहाँ के मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा जिस स्तर पर मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसके बारे में विचार किया जाय और आपको यह भी याद होगा कि श्री गोपालास्वामी आर्यंगर जिस समय वहाँ के प्रधान मंत्री थे उन्होंने अपने राज्य के कानून में और राज्य के घोषणापत्र में यह परिवर्तन किया कि वहाँ के लोगों को कुछ आबादी के आधार पर शिक्षा और नौकरी की सहूलियत हो। जैसा कि हम आये दिन देखते हैं, हर जगह से मांग होती है, हर जगह पिछड़ी जाति के लोगों की मांग है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और आज देश के कोने-कोने से यह मांग उठ रही है। तो काश्मीरी जनता भी अगर उस स्तर पर या उस स्थिति में कोई मांग करती है तो उसका हल आर्थिक हो सकता है। उसका हल साम्प्रदायिक नहीं हो सकता है। साम्प्रदायिक समस्या का इसको रूप देना उचित नहीं है। यह जो बात है कि कुछ हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हुए, तो हिन्दू मुसलमानों के झगड़े कोई काश्मीर में ही हुए हों ऐसी बात नहीं है। रांची में झगड़े हुए और सुरसन बिहार में एक जगह है, वहाँ यह झगड़े हुए और इसके पहले भी वर्षों से हमारे अन्दर जो फूट का बीज बोया गया था अंग्रेजी शासन के द्वारा उसकी वजह से यह आग कहीं-कहीं सुलग जाती है और कहीं-कहीं उसकी चिनगारी दिख जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चिनगारी अंग्रेजों ने सुलगवाई थी—मुझे इसी पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है—

बूट हासन ने बनाया, मैंने एक मजमूँ लिखा,
देश में मजमूँ न फैला, और जूता चल गया।

आज भी हमारे अन्दर कहीं-कहीं ऐसी चिनगारी उठ जाती है, हमको उसका समाधान करना होगा, जिसका सुबूत हमको काश्मीर में मिला है।

आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता—मिर्जा अफसल बेग, जिनकी बहुत-सी

बातें हम ठीक नहीं समझते, जिनके कई काम हमको पसन्द नहीं हैं, लेकिन उनके इलाके अनन्तनाग में कोई चिनगारी नहीं उठी। उन्होंने इस बात का सुबूत दिया कि हम हिन्दू और मुसलमानों में टक्कर नहीं होने देंगे। क्या यह गलत बात है कि हज़रत बल के मन्दिर में, जहाँ पर हज़रत मुहम्मद साहब के बाल रखे हुए हैं, वहाँ पर पचास हजार मुसलमानों ने करार किया कि हम हिन्दू और मुसलमानों में झगड़ा नहीं होने देंगे। इन बातों को सुबूत मान कर ऐसी शक्तियों को हमें प्रस्फुटित करना चाहिये, ऐसी शक्तियों को लेकर हमें चलना चाहिये, ऐसी शक्तियों की मदद करनी चाहिये ताकि हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े कम हों।

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ— श्री प्रकाशवती शास्त्री ने मंगला बांध की बात कही कि प्रधान मंत्री जी ने श्री अयूब को सन्देश भेजा, ऐसा करना ठीक नहीं था। मंगला बांध का सवाल क्या है— आज यही बात मैं इस सदन के सामने रखना चाहती हूँ। इसी सदन में कई बार यह चीज आई, कई बार इस बात की घोषणा की गई कि मंगला डैम बनाने के लिये हमको इतना रुपया देना होगा और इसी सदन के द्वारा वह रुपया दिया गया, इसी सदन ने उसको स्वीकार किया। इन सब बातों का सुबूत क्या निकलता है ? इन सब बातों से यह साफ़ तौर से जाहिर होता है कि मंगला बांध चाहे आज़ाद काश्मीर की सीमा के अन्दर बनाया गया है, लेकिन हमने उसको मान्यता दी। उससे हमको फायदा यह हुआ कि उस बांध के बन जाने के बाद जो पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को नहीं मिल रहा था, अब वह पानी हमको मिलेगा। इसलिये मंगला बांध के बारे में इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की या इस तरह की बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

लेकिन मैं काश्मीर की सरकार से और गृह मंत्री जी से एक अपील ज़रूर कहना चाहती हूँ—आपको याद होगा कि जिस समय काश्मीर

में 144 धारा लागू थी और श्रीनगर में करफ्यू था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सात हजार करफ्यू परमिट्स क्यों ईशू किये गये—सात हजार परमिट्स उस दिन दिये गये। यह डीस-पन शासन के द्वारा क्यों दिखलाया गया, वहाँ का शासन इससे इन्कार नहीं कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि गृह-मंत्री महोदय वहाँ के शासन को मजबूती को बढ़ाने की कोशिश करें, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के शासन द्वारा ऐसा किया जाय। प्रजातान्त्रिक शासन की मजबूती प्रजातान्त्रिक नरीके से ही बढ़ाई जा सकती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you want to postpone the debate? I do not want to postpone it. This will never conclude unless you restrict yourself to your own time. You have exceeded your time. It cannot go on like this. You have so many things to say to the House but it is not possible. Shri Barua.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir, I would have liked the Government to take into consideration the international relations also because the problem of Pakistani infiltration into Kashmir cannot be studied in an isolated manner for it is a part of the calculated strategy on the part of Pakistan to seize Kashmir by force. The latest statement of President Ayub Khan is that there can be no lasting peace between Pakistan and India unless the Kashmir problem is satisfactorily solved. By "satisfactory solution" what he means, I do not know. If he thinks that India should wrap up Kashmir like an easter egg and present it to Pakistan, he is living in a fool's paradise. But, on the other hand, after the Tashkent Pact was signed we were told here that the Kashmir problem has been solved and that there would not be any discussion about Kashmir. Our Prime Minister subsequently told us that Kashmir is not negotiable. If Kashmir is not negotiable, why is it that Shri Chagla, the ex-Foreign Minister, wrote a letter to his Pakistani counterpart on May 6, 1967, proposing that all

the disputes between India and Pakistan, including Kashmir, will be discussed?

Why did you write like that?

Now, I can give you an account how Pakistan has entered into a pact with China for 120 million dollars for supply of arms and ammunition. China is going to implement the pact by 1968. I will not go into all that. It must be said that the policy that has been pursued by this Government, so far as Kashmir is concerned—I mean internal problems—has been a vacillating policy. And there is no policy about it. What happens? The British rulers used to negotiate with the Kashmiri Hindu rulers there. Now, the present Government is following the same policy of negotiating with certain persons and ignoring the people altogether as the British rulers used to do. What have we done? You do not have any firm policy. You want to boost up certain persons ignoring the people of Kashmir. You try to boost up Sheikh Abdullah; you try to boost up Bakshiji. You have boosted up Mr. Sadiq now. That is the policy you have been pursuing there, an unfortunate policy. There is no policy about Kashmir except that of trying to win over the people of Kashmir through certain persons whom you boost up. When you find that they do not serve the purpose, you ignore them and brush them aside. That is the policy you have been pursuing so far.

Kashmir is in ferment today, Kashmir is in trouble, not only internationally but also internally. There are internal foes also. I do not say Muslims of Kashmir are communal minded. But there is a pro-Pakistani element amongst Muslims of Kashmir as there is communal element amongst Hindus there. How has it come? The pro-Pakistani element, that inspiration, has been imported from Pakistan and the inspiration for Hindu communalists has been imported from somewhere in India. Therefore, I say that there should be a sort of general inquiry commission to find out the people who are responsible for this sort of discord in the State of Jammu and Kashmir.

[Shri Hem Barua]

Now, on the 3rd August, 1965, our Home Minister who was then the Defence Minister made a statement in Srinagar that not a single Pakistani infiltrator had come into Srinagar and that the borders had been sealed. On the 12th August, 1965, on the floor of this House, his predecessor, Shri Gulzarilal Nanda, the then Home Minister, made a statement that 12,000 Pakistani infiltrators had come and surrounded Srinagar. Now, my problem is how could 12,000 infiltrators come into Srinagar and surround Srinagar. Was the State Government there sleeping? Were you sleeping here? After the Tashkent Pact was signed, these people went on crying like a bunch of old women requesting Pakistan to withdraw those infiltrators. Why should Pakistan withdraw those infiltrators? It is upto you—you are the guardian of law and order—to push them out. Therefore, I would say that the Government of India should make an inquiry into it. They have, of late, appointed a commission to enquire into the communal holocaust in Ranchi and Gorakhpur and other parts of India and I would say that this should be extended to Jammu and Kashmir also. The present Government of Jammu and Kashmir has appointed a committee of inquiry like that. But I do not want the Central Government to leave the responsibility to the present Government of Jammu and Kashmir because there are great doubts about the present Government of Jammu and Kashmir. Therefore, Mr. Y. B. Chavan should take the responsibility and then he must try to project his image if he is stern and firm ... (Interruption)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I did not say 'No'.

SHRI HEM BARUA : There are some allegations made about the elections also. Shri Bakshiji has just now made the allegations. Those allegations must be enquired into. Wherever there is any pro-Pakistani element in the administration or outside, in the streets, his activities must be curbed and he must be thrown out or else there can

be no restoration of peace in the State of Jammu and Kashmir. When the State of Jammu and Kashmir is in torment, is in ferment, the rest of India is, naturally, in torment and in ferment.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्पीचिंग हुई उनको खूब ध्यानपूर्वक सुना। इस देश में एक बहुत बड़ी कांस्पिरेसी चल रही है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और चीन दोनों मिले हुए हैं और उसके पीछे अंग्रेज हैं और अमरीका भी है। हम और आप यह देख रहे हैं कि जगह-जगह पर वे यह पता लगाना चाहते हैं कि आपकी नसों में पूर्वजों का रक्त बाक़ी है या नहीं। कहीं वह असम में घुस रहे हैं कहीं वह रांची में उपद्रव कर रहे हैं, कहीं गोरखपुर में कर रहे हैं तो कहीं वह कश्मीर में उपद्रव कर रहे हैं। क्या कारण है कि इसके पहले यह बातें नहीं हो रही थीं? आज यह क्यों हो रही हैं तो उसका स्पष्ट कारण यह है कि हम लोग कानमें तेल डाल कर यहां सोये हुए हैं और यह समझ रहे हैं कि विभाजन के बाद हिन्दू, मुसलमानों की समस्या हल हो गयी।

सन् 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया। लेकिन यहां हिन्दू राष्ट्र नहीं हुआ और हिन्दू राष्ट्र कहलाने की बजाय वह सैकुलर स्टेट कहा गया। हालांकि उसे आटोमैटिकली हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए था। हम हिन्दुओं की हिन्दू राष्ट्रियता को साम्प्रदायिकता कहा गया।

इस कारण हमारा जो मनोबल है वह घट रहा है। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की भावना भरी नहीं गई यही कारण है कि देश में हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। हिन्दू जो इस देश की रीढ़ हैं उनको आपने साम्प्रदायिक कह कर उनके मनोबल को घटाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हिन्दू इस देश के राष्ट्रीय नहीं हैं तो कौन हैं? लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद को साम्प्रदायिक कह कर उनके मनोबल को आप घटा रहे हैं।

अर्थात् राष्ट्रीय भावना को घटा रहे हैं और विदेशी तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सब से बड़ा कर्तव्य इस देश का यह है कि देश अपने यहां के नागरिकों को चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों या कोई और अन्य हों, मुसलमान आदि भी इस देश के हो सकते हैं जब वह इस देश को अपनी मातृभूमि व पितृभूमि समझें लेकिन उनकी निष्ठा दूसरे देश के प्रति है तो वे इस देश के नागरिक नहीं हैं और दूसरे देश के माने जायेंगे।

सन् 1947 में जब भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान राज्य का निर्माण हो गया तो यह समझा जाता था कि हिन्दू, मुसलमानों की समस्या हल हो जायगी, लेकिन हमने देखा कि वह समस्या वैसे की वैसे मुंह बायें खड़ी है और वह हल नहीं हो सकी है। पहली गलती जो कांग्रेस सरकार ने कश्मीर के बारे में की वह यह कि भारत में आए रैफ्यूजीज को ले जा कर वहां पर नहीं बसाया। अगर वही इन रैफ्यूजीज को कश्मीर में ले जाकर बसा दिया गया होता तो आज वहां के अल्प-संख्यक हिन्दुओं को यह दिन न बेचना पड़ता। और आज यह कश्मीर की समस्या न होती। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन ने सिक्किम से मुसलमानों को निकाला और उन निकाले गये मुसलमानों को यहां कश्मीर में रैफ्यूजीज की हैसियत से बसाया गया है...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है। मैंने कृपालानी जी को बुलाया है।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मुझे बहुत ही कम समय दिया गया। खैर, जैसी आपकी मरजी।

इसके अलावा वहां कश्मीर में एक और कानून बना हुआ है जिसके कि कारण हम वहां पर कोई भी सम्पत्ति व जायदाद आदि नहीं खरीद सकते लेकिन वहां के लोग डघर आकर जो चाहे खरीद सकते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया। श्री जी० भा० कृपालानी।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे इतनी देरी से बुलाया है कि जो मैं कहना चाहता था वह मैं मूल गया हूं।

कश्मीर के बारे में पहले दिन से हम लोगों की जो पालिसी रही है वह गलत रही है। जब हम ने कहा कि प्लेबिसिट होगी उस दिन से फिर बहुत सी बातें हुईं। वहां एक कांस्टीटुएंट असेम्बली भी बुलायी गयी। कांस्टीटुएंट असेम्बली ने भी कहा कि **Accession of Kashmir with India is complete.** फिर भी हम लोगों ने यह कहा **That is without prejudice to our promise of plebiscite.** अब आप समझिये कि दूसरे आदमी यह बात कैसे समझ सकेंगे जबकि हम खुद ही ऐसा कहते हैं। कांस्टीटुएंट असेम्बली जो एक देश को बनाती है वह कहती है कि **Accession is complete.** लेकिन हम अमरीका आदि देशों से वहां कहते हैं **It is not complete; it is without prejudice to our promise of plebiscite.** इसके तरीके से कई गफलतें हम ने की हैं। फिर क्या करते हो? हम समझते हैं कि वहां एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जायगा तो हमारा सारा सवाल हल हो जायगा। पहले हम ने इतना विश्वास रक्खा शेख अब्दुल्ला में जो यहां यह जो सेक्रेटिरियट है, यह जो साउथ ब्लाक है, यह जो सारा सेक्रेटिरिट का ब्लाक है वहां जाकर वह सेक्रेटरीज को कहते थे कि यह करो और वह न करो और धमकी देकर काम कराते थे कि अगर हमारे कहे के मुताबिक नहीं करोगे तो हम भाई के पास चले जाते हैं। जो भी शेख अब्दुल्ला चाहते थे वहां सेक्रेटिरियट में वह होता था...

एक माननीय सदस्य : भाई कौन ?

श्री जी० भा० कृपालानी : भाई आप हम सब जानते हैं कि उन का कौन है? फिर उस से काम नहीं चला तो दूसरे भाई को शेख साहब के जो दूसरे भाई थे बकशी साहब, उस को बुलाया और जब इन से भी काम नहीं चला तो एक और ही नया आदमी उस जगह पर बुला लिया है। अब जहां तक शेख अब्दुल्ला का सवाल है या वह दूसरे भाई बकशी गुलाम मुहम्मद का सवाल है तो यह दोनों जने तो जनता के आदमी हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो नया आदमी इन के बाद लाया गया है वह किस का आदमी है? उस को जनता से कोई वास्ता ही नहीं है। उस को जनता पहचानती नहीं है। वह माना कि पहले दोनों आदमियों ने बहुत गलतियां कीं, बहुत जुल्म किये तब भी यह जनता के आदमी तो थे लेकिन वह तीसरा जो लाया गया है वह तो जनता का आदमी ही नहीं है। वह तो आप लोगों ने उसे बना दिया क्यों बनाया वह भी समझ में नहीं आता है।

पी० एस० पी० वाले वहां एक अपनी ब्रांच निकालना चाहते थे। उन दिनों मैं पी० एस० पी० का अध्यक्ष था। मैंने कहा कि भाई हुनो, मैं कश्मीर को जानता हूं वहां हम को ब्रांच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह जो सोशलिस्ट हैं यह बड़े आइडि-लिस्ट हैं, अशोक मेहता ने कहा कि नहीं हम वहां पर ब्रांच बनायेंगे। खैर वह बनायी गई और नतीजा यह हुआ कि मार खाकर आया। वह तो वही बात है जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं:

"Fools rush in where angels fear to tread".

मुझ को अपनी जान बचानी थी मैंने कहा कि वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं 1946 के बाद कश्मीर नहीं गया हालांकि मेरे गांधी आश्रम की ब्रांच वहां पर है। वहां गरम खादी बनती है सारे हिन्दुस्तान में जाती है। लेकिन इस दफ्ते मैंने खयाल किया कि 20 साल के बाद मैं उधर जाऊंगा। मैंने वहां जो मेरे काम करने वाले हैं उन को लिखा तो उन्होंने कहा

कि दादा आप यहां मत आइए। दरअसल आप लोग या हम लोग इस कश्मीर की पालिटिक्स को समझ नहीं सकते हैं। इसमें समझिये अशोक मेहता को मार मिली और हमारा एक बड़ा आदमी वहां पर खत्म ही गया मेरा मतलब श्यामाप्रसाद मुखर्जी से है। इसलिए भाई अगर आप लोगों को भी खत्म होना है तो इन बातों में पड़ियेगा। यह बचारे हमारे होम मिनिस्टर वह भी जल्दी से वहां से भाग आये कि कहीं कुछ हो न जाय। दर-हकीकत जैसी यह एक नेटिव स्टेट थी वैसी वह नेटिव स्टेट अभी तक है। यह हमारी गलती ही है कि हम कुछ चंद आदमियों के ऊपर विश्वास रखकर बैठते हैं। हम समझते हैं कि इस चीफ मिनिस्टर को हटा दिया दूसरे को उस की जगह ले आये हमारा सवाल हल होगा और हम जनता को एप्रोच नहीं करते। पैसा तुरन्त हम देते हैं बाकी वह कहा जाता है उस का हम को खयाल नहीं है। 6 आने किलो चावल मिलता है काश्मीर में और यहां डेढ़ २० किलो भी नहीं मिलता है। वहां एम०ए० तक फ्री एजुकेशन है, लेकिन यहां नहीं है। इस ब्राइवरी से आप काम नहीं चला सकते। अगर कोई कहता है कि काश्मीर में कम्यूनलिज्म नहीं है, तो यह झूठ है। कम्यूनलिज्म वहां है। और कैसे नहीं हो सकता है? जब 12 हजार इन्फिट्रटर्स वहां आ गये तब भी आप समझते हैं कि वहां की जनता में कोई कम्यूनलिज्म नहीं है? यह हो ही नहीं सकता। करोड़ों रुपये पाकिस्तान खर्च करता है तो क्या वह बेवकूफ है? वहां उस के एजेन्ट्स बैठे हुए हैं। आप तो उन को जानते भी नहीं हैं। वह वहां पर काम कर रहे हैं। शायद वह आप की आर्मी में भी काम करते हों। यह कहना कि वहां कम्यूनलिज्म है ही नहीं, यह असलियत से आंखें बन्द करना है। यह जरूर है कि काश्मीर में कम्यूनलिज्म शुरू से रहा नहीं है। काश्मीर के हिन्दू मुसलमान आपस में भाई चारा कर के रहते थे। लेकिन यह कहना कि वहां अभी कम्यूनलिज्म है ही नहीं, यह ठीक नहीं है।

To say that the Muslim mind has not been affected at all by the propaganda of Pakistan is to close one's eyes to the facts. It is a fact and it is there. But how are we to counteract it? हम इस तरह से काउंटरएक्ट कर सकते हैं कि हमारे आदमी वहां बसाये जायें, आप जो पैसा खर्च करते हैं वह वहां के आदिमियों के पास जाये, हम गरीबों को आगे बढ़ायें। लेकिन वह आप करेंगे कैसे? जब आप यहां नहीं कर सकते हैं तो वहां कैसे करेंगे?

यहां भी हम कुछ खास-खास आदिमियों पर भरोसा कर के बैठे हुए हैं। यह तो हमारी डिमोक्रेसी का नमूना है। यूनिवर्सल वोट विथ ए-यूनिवर्सल इन्फोर्सेस, ऐसा हमारा हाल है। अगर आप इस सवाल का सोल्यूशन चाहते हैं तो यह प्रेजिडेंट्स राज्य से नहीं होगा। आज एक कालम को संविधान में से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। जनता के पास आप के आदमी जायें, उन की खिदमत करें। सोशल रिफार्मस जायें, कंस्ट्रिक्टिव वर्क्स जायें, उन लोगों की गुरबत दूर करें, तब यह मसला हल हो सकता है। खाली एक चीफ मिनिस्टर के बदलने से काम नहीं चलेगा। इस से तो रजवाड़ों की पालिटिक्स चलती है यह आप जान लीजिये। वहां रजवाड़ों की पालिटिक्स चलती है, वहां डिमोक्रेसी नहीं चलती है। इस को आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। बख्शी यह बात सच कहते थे कि वहां डिमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उन के जमाने में भी कहां डिमोक्रेसी थी? माफ कीजिये, क्योंकि हम तो अपना आदना रखते हैं। उन का ही जमाना था कि जब हमारा गुजराती भाई वहां पीटा गया अशोक मेहता। अशोक मेहता को पीटने में क्या लगता है? कोई भी पीट सकता है। इस में कौन सी बहादुरी है? (हंसी) जब मैं कोई रास्ता बतलाता हूं तो उस पर यहां लोग हंसने लगते हैं। मैं क्या करूं? मैं आप से कहूंगा कि मेहरबानी कर के जो पैसा आप खर्च करते हैं

उस को ठीकसे खर्च कीजिये। वह फुजूल खर्च होता है। आप इस तरह से खर्च करें कि जनता के पास जाये।

दूसरी बात जो आप को करनी है वह यह कि आप के जो फर्स्ट क्लास ऐडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन को आप काश्मीर में भेजिये। अगर काश्मीरियों को जगह देनी है तो यहां ला कर बिठलाइये। अगर आप यह करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आप किसी न किसी तरह का सोल्यूशन हासिल कर लेंगे। अगर आप यह नहीं करेंगे और काश्मीरी अफसरों के हाथ में सब चीजें दे देंगे तो आप का काम नहीं चलेगा।

Let them go to the people and send their best administrators from here to that place and employ those people who want some employment, here. There is no other solution.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : The motion moved by Shri Prakash Vir Shastri was, really speaking, connected with the situation arising out of the serious threat to national security posed by the recent influx of infiltrators into Kashmir. But on the basis of this Motion, naturally this discussion covered a very wide area. It was quite useful to know the views of all the most important parties and also some important leaders such as Dada Kripalani.

I do not propose to reply to all the points raised because it is difficult to reply to them in a small debate like this in a very short speech. The basic point I would like to touch upon concerns some of the issues raised by Shri Prakash Vir Shastri and Bakshi Ghulam Mohammed. The first question Shri Shastri asked me was : what have I done or what is being done in regard to some of the assurances I gave when I visited Kashmir during the Pandits' agitation? I had assured him on two or three important points. One was that the question of excesses committed by the police during the agitation should be inquired into by an officer to be nominated by me from here. I would like to tell the House that the

[Shri Y. B. Chavan]

Director of the CBI, Shri Kohli, has been nominated by me, and the nomination has been accepted by the Chief Minister of Kashmir, to go into this question of police excesses during the agitation.

The other point was that there were certain grievances of the Pandits. On the question of imbalances, economic imbalance, imbalances in employment etc. it was necessary that some sort of a high power committee should go into them. It is now common knowledge that a Committee under the chairmanship of Shri Gajendragadkar has been appointed to be assisted by two other colleagues of his, which will go into this question. Naturally, they will go into the question of the imbalances in development, economic questions and so on. People with the experience of Justice Gajendragadkar, Shri Shankar Prasad and Shri Tyabji are on the Committee and I think the recommendations made by this Committee will be a very useful document both for the Government of Kashmir and also for public opinion in India as a whole. These were the two basic issues on which I gave an assurance and this has been acted upon.

Naturally, I do not want to go into the question of the Hindu girl being married to a Muslim gentleman because it is *sub judice*.

SHRI HEM BARUA : It is a natural thing.

SHRI J. B. KRIPALANI : May I suggest that in such cases the girl is always kept with neutral persons? Has that been done in this case?

SHRI Y. B. CHAVAN : If it were done, I would certainly have welcomed it.

SHRI J. B. KRIPALANI : He must use his influence to have that done.

SHRI BAL RAJ MADHOK : He wanted to do, but could not get done.

SHRI Y. B. CHAVAN : The court was seized of the whole matter. The court could do that. But my difficulty

was that I could not interfere with the judicial processes when the court had taken cognisance of the matter. Naturally the judicial processes had to be allowed to proceed further.

SHRI J. B. KRIPALANI : What I mean to say is that such a step is customary. When there is a dispute about a girl, for the time being the girl is kept in some neutral place.

SHRI Y. B. CHAVAN : I understand that.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : What is the use of understanding if it is not executed?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not want to go into the facts of the case. These are matters on which there are two different views. As the matter is before the court, I do not want to express any view on this matter.

SHRI J. B. KRIPALANI : It is a question of procedure only.

SHRI Y. B. CHAVAN : I know it is a question of procedure. Naturally they follow it. I certainly would welcome Acharya Kripalani's suggestion, which really speaking, if the court accepted it, would have saved many troubles not only for the girl, but possibly for the whole of Kashmir. This is one aspect of the matter to which he made reference.

I would like to mention another aspect, and that is about elections that the hon. member mentioned. Shri Bakshi was not then a Member of Parliament, but, as an old colleague, he wrote to me about it, and naturally I conveyed our feelings about it, our thinking about it, to the Chief Minister of Kashmir. This whole question is now in a way before the tribunals, before the High Court Judges, because most of these matters are the subject matter of election petitions.

I know that election petitions are delayed, I quite concede that point. I do not want to hold a brief for anybody. Delay is delay, and delay in election petitions is not very good, I must concede that, but after these allegations

were made, the representatives of the Election Commissioner went to Kashmir, Shri Bakshi himself made a reference to it, and they themselves suggested that it is much better that the election law of Kashmir is brought in line with Indian law, with the law of the rest of the country. Naturally that could not be done during the election period, that was undertaken immediately after that. As to why it was not done in the March or June session, we know the fate of the legislative programmes in our sessions.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : That was passed in the August-September session.

SHRI Y. B. CHAVAN : Possibly they might have thought of it, but merely the desire of the Government does not help it, but it was certainly completed in September, and I must say that though some delay was involved in it, this is perhaps the most welcome thing that has happened in Kashmir, that their election law is now on the lines of the all-India election law.

SHRI NATH PAI (Rajapur) . On the lines, or on a par with ?

SHRI Y. B. CHAVAN : On a par, in all respects, particularly in matters of election petitions. Formerly it was a tribunal, but it is the High Court Judge who is going to hear all these petitions.

श्री जी० बा० कृपालानी : बक्शी जी बहुत दूरअदेश हैं। वह जानते थे कि अस्मिन्वर्ती के वास्ते खड़े होंगे तो उनके कागज रद्द हो जायेंगे, इसी लिए यहाँ भाग आए।

SHRI Y. B. CHAVAN : About that wisdom, I am not making comments. It was Acharya Kripalani's comment, it was not my comment.

So, after this election law was amended, we received proposals from the Kashmir Government recently. I had assured hon. member Shri Bakshi that immediately I received these proposals,

within ten days I will see that they are through, and I want to tell him that the President has issued the necessary orders about the appointment of those Judges. I do not know if those Judges will be the only Judges who will look after the election petitions, these are the additional Judges, they are called *ad hoc* Judges. Whether they will deal with only election petitions or other normal judicial work, I do not know, but these appointments have been made. As far as this point is concerned, I have acted on that, and I wanted to make it clear.

About the development programme of the Jammu and Kashmir Government, many aspects were raised, why expenditure was made on this and that. I have not got all the information from the Jammu and Kashmir Government to reply to all the points. Therefore I am not saying one way or the other, but I know one thing which I must say, and that is about the attitude of the Jammu and Kashmir Government about infiltrators, because I really came prepared for that, because this was the major aspect on which the motion was moved.

There I must say that this is a fact of life which has to be accepted, it is no use saying whether there is any communalism or not, I would not go into that. Acharya Kripalani has said much about it, it is much better that we take a realistic attitude. It is very difficult to say that there is no communalism, but one thing that must be said is that when there were violent communal clashes in the other parts of India, even though there were communal feelings—I cannot say there were no communal feelings when I visited Kashmir—there was absolutely no communal clash between Hindus and Muslims. That must be accepted. No Hindu was attacked by a Muslim; no Muslim was attacked by a Hindu. There is something in the Kashmir tradition which we must accept, Who can say that there may not be communal feelings? But the point is, so far as day to day work with each other is concerned, Kashmir has some lesson to offer us. That must be conceded.

[Shri Y. B. Chavan]

At the same time, I must say that so far as I have understood the Kashmir situation, certainly there is some sort of minority complex among the people. I had long talks and of course, it is rather very risky to make some sort of a general assessment about this. But I found everybody in Kashmir suffering from some sort of minority complex. A Hindu in Jammu feels he is a minority in Kashmir. Muslim in Kashmir feels he is a minority in Jammu. A Muslim in Kashmir Valley feels he is a minority in India. That sort of peculiar complex is there, which needs some sort of treatment and some sort of understanding. Therefore, I would say that any easy solutions suggested here and there are not the right solutions.

I am not going into the other aspects of it like the defence aspect, etc. I do not know who was a better Prime Minister there or Chief Minister there—Sheikh, Bakshi or Mr. Sadiq. I do not want to go into comparisons. But one must concede that Mr. Sadiq is a completely secular person, who has faith in secularism. Politically he is a liberal person. I know there are certainly some restrictions in civil liberty, because of certain inherent conditions in Kashmir. It is not something which I can say is very ideal. That is also because of certain local conditions there. But Mr. Sadiq is certainly a democrat and a liberal person. I must say after Tashkent Declaration, nearly 35 spy rings were broken by the Kashmir Government and a large number of people were arrested for spying activities. Some illegal arms which were dumped in different parts of Kashmir were also unearthed and confiscated. Some prosecutions have also been launched. Therefore, as far as the national security aspect is concerned, Mr. Sadiq himself is taking as keen an interest as any of his predecessors. This must be said to the credit of the present Kashmir Government. What are the other defects of the Kashmir Government, this is not the occasion to go into them. But it cannot be said that they have done nothing about development. As Defence Minister, in 1965 I had occasion to discuss many developmental

aspects of those areas. I must say that it is not merely a question of what happens in Srinagar. Really speaking, the most important thing was what was happening in the interior, rural areas and in those border areas from which the infiltrators were threatening to come in. From that point of view, the Sadiq Government certainly has taken more important steps and definite progress has been achieved in those areas. I have seen it with my own eyes. It is not merely a question of quoting statistics here and there. He has got that democratic approach.

I entirely agree with Acharya Kripalani that the only solution to solve the Kashmir problem is to go to the people. I have no doubt about it; it is not only through this man or that man that we can solve the problem. Ultimately we have to go to the people and win their hearts. It is the people of Kashmir who are more important, not some small document to which Mr. Madhok referred. He may be believing in that. He has every right to believe in what he thinks to be right.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I do not minimise the importance of the people, but the legal position also is there. We cannot ignore that.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am glad that you do that. Talking about political and democratic matters how can you forget the people. How can you say, if you do not want you go to Pakistan? No. They will have to remain in India. If they are less patriotic we will have to work with them, create a feeling of friendliness and make them believe in India's future and further participation in the Indian common life. That is, really speaking, what will have to be done. This is the approach we have to pursue in these matters. I am not holding any brief for any particular government, but my only point is that as far as the national security aspect is concerned we are alive.

I must make a personal explanation because a reference was made to what I said before the infiltrators came in August 1965. I think it was on the 1st or 2nd.

SHRI HEM BARUA : It was on 3rd August.

SHRI Y. B. CHAVAN : You must have read it on the 3rd. I made the speech on the 1st or 2nd. The only question that I answered was, what was the trend of infiltrators in the last two weeks. I had explained that time, in that statement that I made, that in recent weeks there was a reduction in the infiltrators.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Fine clarification.

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not a question of fine explanation. I was giving an explanation based on facts. That was a matter of fact. At the same time I had said, it does not mean there is no danger of infiltrators. Somebody cannot just try to take a sentence out of context and throw it at my face just now. But the fact remains.

Sadiq's one contribution we must accept. When there was such a very serious threat to Kashmir in 1965, when such a large number of infiltrators came in, during that time he maintained law and order position in Kashmir in such a way that it is something very creditable. We must give him whatever is due to him.

श्री राम गोपाल शालवाले : उसका श्रेय तो भारतीय सेना को है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लेकिन भारतीय सेना के साथ लोगों का जो को-आपरेशन रहा है, वह भी मानना चाहिए ।

श्री राम गोपाल शालवाले : आज की स्थिति में सादिक साहब की मौजूदगी में हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहते हैं ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I must say that this way of putting problems is creating further problems. It is not a question whether this Government is pro-Muslim or pro-Hindu. That is why I made an assertive statement in the very beginning that one good thing about Sadiq is that he is hundred per

cent secular (*Interruption*). I know there are feelings of grievances of pandits. I never say no to it. The question of pandits need to be handled more carefully, more sympathetically. There is that feeling. I understand that that feeling is there. I do not want to say that Sadiq has this feeling and therefore the pandits have got this grievance.

SHRI BAL RAJ MADHOK : The grievance is not against Sadiq as such, it is against Sadiq Government.

SHRI Y. B. CHAVAN : Ultimately the attitude of the leader of the Government is reflected in the Government also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about Pakistani slogans raised in Jammu and Kashmir ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As I said, I do not say there are no people who certainly would not welcome Ayub's regime in Kashmir. I have not said that. That would be closing eyes to realities in Kashmir. There are some people.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why don't you deal with them firmly ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Certainly they will have to be dealt with firmly. The existence of a few such people need not excite us to feel that everybody thinks the same way. There are some people. I do not take the position that there is nobody in Kashmir who does not want Pakistani infiltration in Jammu and Kashmir. There are some such people. But we must know them, we must shake them, we must persuade them, we must try to convert them, not in the other sense, but converting their point of view. We should know who they are and carefully watch them. That also we are doing. And I would like to tell you that; not that we are unaware of it.

श्री राम गोपाल शालवाले : सादिक के रहते हुए वह विचार-धारा नहीं बदल सकती है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : There I disagree with my hon. friend. On whether there should be President's Rule, I was, really speaking, very sad when this suggestion came from the hon. Member, Shri Bakshi.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : I did not suggest the dismissal of the Sadiq Government because you would not accept it.

मैंने जो तीसरी बात कही है, उसके साथ तो आपको इतिफाक होगा।

SHRI Y. B. CHAVAN : I only wanted to know it. You did not make that suggestion because I would not accept it or because you did not believe in India?

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : That is politics.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is my main point. I certainly would not accept such a suggestion. Of course, if there is a constitutional failure, that is a different matter.

श्री गुलाम मुहम्मद बक्शी : क्या वहाँ भी हम डिफेक्शन शुरू करें? वहाँ भी हो सकते हैं।

SHRI Y. B. CHAVAN : I would never advise anybody to defect or start defections.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : I do not want to enter into an argument. My submission is that President's Rule will not be acceptable to you and the dismissal of that Government is difficult for you, as you are pleased. So, my suggestion is this.

मैंने यह अर्ज किया है कि आप इल्लेक्शन पैटीशनर का फ्रीसला मार्च के एंड तक करा दीजिए।

SHRI Y. B. CHAVAN : I started with that. But he stated that the bye-elections should be held within a certain time, presuming that the election petitions are already disposed of. The election petitions are yet to be heard. Naturally, when they are heard, the provisions of the rules will apply. The Election Commissioner will . . .

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : It has already taken 9 months.

SHRI Y. B. CHAVAN : I gave you the reasons for it. But I do not justify the delay. I said that delay in an election petition is the worst thing that can happen in a democracy. But I gave you the exact reasons. The Act had to be amended. After amending the Act, within two months two judges are appointed, who can look into the election petitions.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Would you make a request to the Sadiq Government to expedite it now?

SHRI Y. B. CHAVAN : Now it is not in the hands of the Sadiq Government; it is now in the hands of the High Court Judges. In this matter the judiciary is completely separate; it is completely independent. Therefore, it is not a question of telling Sadiq about it. Now, it is a question for the High Court Judges to expedite this thing, and I have no doubt that they will certainly do whatever is necessary to expedite these things.

SHRI D. N. PATODIA : How do you explain the widespread emergence of pro-Pakistani elements in Kashmir?

SHRI Y. B. CHAVAN : There is no widespread emergence of such elements.

SHRI D. N. PATODIA : They are parading in the streets with such slogans.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Pro-Pakistani slogans have been raised in the streets of Srinagar.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is not true. And I am sure that even Bakshi cannot claim that during his regime there were no pro-Pakistani slogans raised by anybody. That would be an incorrect statement to make.

SHRI HEM BARUA : It is reported that in Kashmir pro-Pakistani slogans are raised by some people. It is also reported that in Calcutta pro-Mao

slogans are shouted by some people. But suppose a man in the streets of Peking says "Chavan Zindabad" he would be reduced to pulp by the Red Guards. What are you doing in the matter ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I share the feelings of my hon. friend. But the only point that I would like to stress is this, that it would be wrong to say that the pro-Pakistani slogans have started only now because, then, it becomes party politics. There is something like Kashmir politics. There is something like Indian politics which is involved in Kashmir, and party politics is something different. Therefore, if you want to criticise the Kashmir Government today, I can understand a criticism based on national issues. That certainly one can do. But when there is this partisan attitude, as far as politics is concerned, I would like to say that the criticism was very unfair.

19 hrs.

SHRI J. B. KRIPALANI : Will you take into consideration my last suggestion ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am glad, he has reminded me of it. I forgot that point about sending the best administrators to Kashmir. This has been continuously done in the last two years. The best officers have been selected by the Sadiq Government. It is not that we send them there but the Sadiq Government themselves have asked for the best officers and they have always welcomed the good officers.

SHRI D. N. PATODIA : I would not like to name the persons but I have been told by authoritative sources . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, please. Shri Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है कि बिल्ली को आते हुए देख कर कबूतर आंखें मींच कर बैठ गया और सोचने लगा कि उसका खतरा टल गया . . . (व्यवधान) . . . ठीक यही स्थिति इस सरकार की है।

भारत सरकार जानबूझ कर अगर खतरे की ओर से अपनी आंखें बन्द कर ले और यह समझे कि कोई संकट नहीं है तब तो कोई भी युक्ति देने की आवश्यकता ही नहीं है और इतना लम्बा चौड़ा वाद-विवाद करने की भी यहां आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यदि भारत सरकार संकट को संकट समझती है और संकट का उपाय ढूँढने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है दलीय स्तर पर प्रयास नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि गंभीरता से सोचना देश के हित में भी होगा और आने वाले भविष्य के हित में भी होगा।

इस वाद-विवाद में और सदस्यों की चर्चा छोड़ते हुए जो सरकारी कृषियों से दो मिनिस्टर बोले हैं मैं केवल उन्हीं की चर्चा करना चाहता हूँ। कांग्रेसी सदस्यों की बात को मैं छोड़ता हूँ। इस में जो वाणिज्य मंत्रालय में मंत्री हैं श्री कुरेशी साहब उन का जो भाषण था वह मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि वह काश्मीर के निवासी थे। मुझे इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनका निर्विरोध वहां पर निर्वाचन हुआ है। जिन लोगों के नामिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं उन में उपाध्यक्ष जी, आप को याद होगा इसी सदन के एक माननीय सदस्य थे जिन का नाम था पंडित श्याम लाल सराफ़ उन का नामजदगी पत्र केवल इस आधार पर रद्द किया गया कि उन्होंने इलेक्शन आफिसर के सामने खड़े हो कर शपथ नहीं ली जब कि उनका वह शपथ पत्र पहले वहां था। उस को किस ढंग से हटाया गया, यह सब बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उन के स्थान पर यह साहब चुन कर आये हुए हैं जो काश्मीर की ओर से खड़े हो कर और यहां वकालत कर रहे थे। मैं उन के पुराने इतिहास में भी नहीं जाना चाहता कि पीछे जो चार पांच साल तक जेल के अन्दर बह रहे किस आधार पर रहे? वह बात तो छोड़ता हूँ। लेकिन आज मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूँ खास तौर से गृह मंत्री श्री चह्माण से कि इधर से अगर किसी सदस्य की ओर से भूल से भी कुछ

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

ऐसा कह दिया जाता—जिसका पाकिस्तान उसका अर्थ करता तो आपको कष्ट होता। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं अपने एक-एक शब्द की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि यहाँ जो कुछ आज कहा जा रहा है वह भारत के समाचारपत्रों और जनता के लिये ही नहीं है। इस के एक-एक शब्द को पाकिस्तान देखेगा कि हमारे हित में कौन से शब्द का प्रयोग हो सकता है? इसी आधार पर मैंने इस चर्चा में एक-एक शब्द को बड़ा नाप और तोल कर प्रयोग किया। अगर मेरे किसी शब्द से या मेरे पूरे भाषण में यह झलक आई हो कि काश्मीर के अन्दर मुसलमानों में इस प्रकार की भावना आ गई है कि काश्मीर के पूरे मुसलमान प्रो-पाकिस्तानी हो गए हैं या काश्मीर के हिन्दुओं में इस प्रकार की भावना हो गई है तो मैं भरी सभा में, भूल से भी कोई ऐसी बात अगर आ गई हो, तो उसे वापस लेने के लिये तैयार हूँ। मैंने इन शब्दों का जान-बूझकर प्रयोग किया था कि पिछले 20 वर्षों में काश्मीर में कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ। काश्मीर के अन्दर हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई की तरह मिल कर रहते रहे इस अगस्त 1967 के कांड के पहले मेरे इन सारी बातों को कहने के बावजूद आप के पीछे बैठे हुए मिनिस्टर कहलाने वाले व्यक्ति कुरेशी ने इस सारी चर्चा को इस रंग में रंगने की कोशिश की कि काश्मीर के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उन की नीयत पर शक किया जा रहा है। क्या इसी प्रकार के वकील आप तैयार करके लाते हैं अपने पक्ष को बचाने के लिए? यहाँ तक भी वह वकील साहब कह गए यहाँ पर खड़े हो कर जिन्हें बहुत जिम्मेदारी का ओहदा आप ने सौंप रखा है, कि अगर काश्मीर के लोगों का दिल आप को जीतना है तो उन को आने-जाने की सुविधा दीजिए, उन को नौकरी की सुविधा दीजिये। क्या कहलवाना चाहते हैं आप उन के मुंह से कि काश्मीर के लोगों को नौकरी की सुविधा भारत में नहीं है? यह आप के पीछे बैठा एक मिनिस्टर यह कह रहा है और उस को

आप अपना पक्ष लेने के लिये यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं? मैं फिर आप को कहता हूँ कि मित्र की पहचान करना सीखिये। हृदय से मित्र कौन है? इस तरह के मित्रों की पहचान से आप को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। मैं इस बात को और इस में अधिक विस्तार में नहीं कहना चाहता।

जहाँ तक श्री यशवंत राव चव्हाण का संबंध है उन्होंने जितने भी प्वाइंट्स मैंने या दूसरे सदस्यों ने मुख्य रूप से रखे, मैं नहीं कह सकता कि विस्तार-भव से उन्होंने उन को नहीं छोड़ा या क्या बजह थी? लेकिन मैं तो उस को यों मानता हूँ कि उस के अन्दर बहुत कुछ सच्चाई है और इसीलिये उन बातों को खोलना उन्होंने उचित नहीं समझा प्याज के छिलके को हटाने से बदबू ही आयेगी उस के अन्दर सुगन्ध नहीं आ सकती। वह इन तमाम बातों को जानते हैं। लेकिन इन सारी बातों के जानने के बावजूद भी गृह मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण ने अपने तीन आश्वासनों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाते हुए उसे अपने विश्वास में लेने की कोशिश की यदि वह 2 सितम्बर को और 3 सितम्बर को श्रीनगर के अन्दर उन लोगों को जो कह कर आये थे, आज कम से कम इतने दिन बाद यह भी कह देते कि अभी तक अगर उस लड़की का न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हो पाया है तो क्योंकि काश्मीर एक भारत का अंग ही नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र है और वहाँ की इस प्रकार की घटना का भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है। हम प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस का समाधान हो और जब तक न्यायालय उस का निर्णय नहीं देता तब तक उस लड़की को किसी निष्पक्ष व्यक्ति या निष्पक्ष आश्रम के अन्दर रखा जायगा। अगर यह बात कह देते तो मालूम पड़ता कि गृह-मंत्री को उस का ध्यान है। सादिक साहब की प्रशंसा के शब्द कहते जाना, सादिक साहब को प्रमाण-पत्र देने जाना यह क्या है? जब आप ने उन को बैठाया है तो आज आप उन को प्रमाण-पत्र नहीं देंगे तो क्या मैं उन को प्रमाण-पत्र दूंगा।

जब आप ने उन को बैठाया है तो आप तो उन को प्रमाण पत्र देंगे ही।

परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनि : आपने उन को बैठाया और आप ही आज बैठा करके उनकी प्रशंसा करें इस का क्या अर्थ होता है? हमें भी इस बात से प्रसन्नता नहीं होती कि देश में किसी हिस्से पर राष्ट्रपति शासन लादा जाय। लेकिन जब जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार वहाँ पर विधिवत गठित न हुई हो और जनतंत्र वहाँ पर कलंकित हो रहा हो, लोगों के हितों की सुरक्षा वहाँ पर न हो और इस प्रकार का वातावरण बनता चला जाय जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों विस्फोटक स्थिति पैदा कर दें या पाकिस्तान के हाथ मजबूत करे, तो क्यों आप ने अपने विधान में यह धारा लगायी थी कि जम्मू काश्मीर में आवश्यकता

पड़ने पर राष्ट्रपति को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, या राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है? क्या इस से बड़ कर भी भयंकर स्थिति वहाँ पर हो सकती है? मैं अंत में केवल एक ही लाइन कह कर बैठ जाता हूँ कि गृह-मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण इस बात का विचार करें कि वह यह वक्तव्य दे कर सदन को सन्तुष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता की कुछ पंक्तियाँ बह जोड़ रहे हैं। भारत सरकार की इस उपेक्षा भरी नीति को आज नहीं तो कल आने वाली हमारी संतति कभी क्षमा नहीं कर सकती।

19.10 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 1, 1967/Agrahayana 10, 1889 (Saka).